हिंदी दैनिक

कलम की पहल

PRGI NO. UAHIN/25/A1323

वर्ष : 02 अंक : 142 पृष्ठ : 08 मूल्य : 1 रूपए नैनीताल, मंगलवार, 10 नवंबर, 2026

E-mail: kalamkipahaluk@gmail.com Website: kalamkipahal.com

मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस पर भराड़ीसैंण में कीं 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं, विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को दोहराया

राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखण्ड का विकास सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

आंगनबाड़ी, आशा कार्यकत्रियों, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में होगी वृद्धि

राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित होगी कैबिनेट समिति





मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा भवन परिसर, भराड़ीसैंण (गैरसैंण), जनपद चमोली में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने 26 वर्षों की विकास यात्रा में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 51 सीमांत गांवों में लगभग 200 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं तथा 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत तथा सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों की अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। सैन्य धाम का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों तथा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर उत्तराखण्ड का गौरव बढ़ाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे निर्णय जनहित में लिए गए हैं।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों तथा सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक श्री त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। परेड में आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस एवं एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में श्री जवाहर सिंह, श्रीमती गीता देवी, श्रीमती वंदना देवी, श्री मोहन सिंह एवं श्री आनंद सिंह को अनुदान प्रदान किया गया। मिशन कीवी के अंतर्गत श्री आनंद सिंह एवं श्री गंभीर सिंह को 2.10-2.10 लाख तथा श्री दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये के चेक दिए गए। श्री जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए 2 लाख रुपये प्रदान किए गए।

उद्योग विभाग की योजनाओं के अंतर्गत श्री योगेंद्र सिंह को एक लाख, श्री त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, श्री राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये तथा श्री हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई। स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए 4-4 लाख रुपये की सहायता दी गई। कृषकों को पावर वीडर अनुदान तथा किसान भूषण एवं किसान श्री पुरस्कार प्रदान किए गए। महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी एवं अटल आवास योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री ने खेल प्रतिभाओं कु. आरुषि नेगी, कु. महक रावत एवं श्री हर्षवर्धन बिष्ट को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार जनकल्याण, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा लोकसंस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस पर निम्नलिखित 13 घोषणाएं कीं–

1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
2. आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
3. भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
4. लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार एवं नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
5. वन्यजीवों के हमले में घायलों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
6. प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
7. अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
8. प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
9. बुजुर्गों, दिव्यांगजनों एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 'अपुणि सरकार' पोर्टल की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में अधिक सरल एवं प्रभावी बनाई जाएगी।
10. छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
11. लोकसंस्कृति एवं लोकभाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी एवं स्वर्गीय श्री चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।
12. प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की जाएगी।
13. राज्य आंदोलनकारियों की मांगों एवं समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन तथा आश्रितों को प्रमाणपत्र देने संबंधी विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस अवसर पर जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री श्री भरत सिंह चौधरी, विधायक श्री अनिल नौटियाल एवं श्री भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री मोहन भंडारी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष श्री गजेन्द्र सिंह रावत, दर्जाधारी राज्यमंत्री श्री रामचन्द्र गौड़, श्री हरक सिंह नेगी एवं श्री बलबीर घुनियाल, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती दुर्गा देवी, श्री अरुण मैठाणी, श्री विनोद कनवासी, जिलाधिकारी श्री गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री सुरजीत सिंह पंवार तथा मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी सहित राज्य आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

दिसंबर 2028 तक गुजरात को नशा-मुक्त बनाना है: अमित शाह



नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अहमदाबाद के बडाज इलाके में 700 से अधिक नवनिर्मित आवासों का उद्घाटन किया और 1,024 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को शहर की जनता को समर्पित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने दीपावली और नए साल की शुभकामनाएं दीं।

अमित शाह ने बताया कि आज करीब 1,400 करोड़ रुपये के कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इनमें से लगभग 1,100 करोड़ रुपये की परियोजनाएं अहमदाबाद नगर निगम की हैं, जबकि सड़क एवं भवन विभाग और भारत सरकार की करीब 400 करोड़ रुपये की परियोजनाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या आज शुरू की गई।

गृह मंत्री ने रामापीर टेकरा का जिक्र करते हुए कहा कि उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत यहीं से हुई थी। 1985 में जब वे वोटर कार्ड और पर्चियां बांटने जाते थे, तब वहां गंदा नाला बहता था, पीने के पानी का इंतजाम नहीं था, बीमारियां फैलती थीं और छोटे-मोटे अपराध आम थे।

उन्होंने याद दिलाया कि 2007 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तब झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को पक्के घर देने की योजना शुरू की गई थी। अब रामापीर टेकरा के निवासियों को प्राइवेट बिल्डरों जैसे साफ-सुथरे फ्लैट मिल रहे हैं, जिनमें पंखे तक लगे हैं। पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने पर परिसर में 55,000 से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन, लाइब्रेरी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

अमित शाह ने बोपल-घुमा में एक पंप हाउस के भूमि पूजन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बारिश के समय वहां घरों में पानी घुस जाता है। यह इलाका उनका और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का चुनाव क्षेत्र है। उन्होंने वादा किया था कि अब वहां पानी जमा नहीं होगा।

काली चौदस के अवसर पर हुई बैठक का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा नशा-मुक्ति को बताया। उन्होंने कहा, 'आप बस एक कॉल (1033) करें और गुजरात सरकार नशा बेचने वालों को जेल में डाल देगी। नशा हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देता है।

दिवाली के बाद दिल्ली बनी गैस चैंबर!

PM 10 का स्तर 3000 के पार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में बीती रात (08 नवंबर) को दीपावली पर लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े, जिसके बाद दिल्ली एक तरह से गैस चैंबर बन गई. आज (09 नवंबर) सुबह दिल्ली में आसमान में हर तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आया. एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव पड़ताल में सामने आया है कि दीपावली में पटाखे जलने के बाद रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में दिल्ली के कई इलाकों में PM 10 प्रदूषण का स्तर 1000 से लेकर 3000 तक पहुंच गया. पड़ताल में ये भी सामने आया कि भारत सरकार की सीपीसीबी ने जिस समय दिल्ली में PM 10 अपने प्रचंड स्तर पर था उस समय का डेटा अपने ऐप पर जारी नहीं किया और सीधा उस समय का डेटा दिखाया जब PM 10 का स्तर 500 के नीचे चला गया. DPCC के आकड़ों के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार में रात 12 बजे PM 10 प्रदूषण का स्तर 3 हजार पार कर गया और रात 2 बजे PM 10 अपने उच्चतम स्तर 3 हजार 490 पर था. लुटियंस दिल्ली में स्थित मंदिर मार्ग पर PM 10 रात 2 बजे दो हजार क्रॉस करके 2 हज़ार 506 तक पहुंच गया तो वहीं सुबह 4 बजे अपने उच्चतम स्तर 3 हजार 124 पर दर्ज हुआ. इसके साथ ही पटपड़गंज में रात 12 बजे PM 10 का स्तर 2 हजार 889 था. नजफगढ़ में PM 10 का स्तर रात 2 बजे अपने उच्चतम स्तर 2 हज़ार 59 पर था, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम पर रात 2 बजे PM 10 अपने उच्चतम स्तर 1900 पर था, सोनिया विहार में रात 12 3 बजे PM 10 अपने उच्चतम स्तर 1700 पर था. विवेक विहार में रात 12 बजे और 2 बजे PM 10 का स्तर 1185 था. राजधानी दिल्ली में आज सुबह साढ़े 8 बजे AQI बेहद खराब श्रेणी में 368 था. उस वक्त काम कर रहे 59 में से 54 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन के आकड़ों के मुताबिक 15 स्टेशन पर AQI गंभीर श्रेणी में यानी 400 के पार दर्ज हुआ. यह आंकड़ा सुबह 8 बजे दर्ज हुआ था. वहीं 35 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन पर AQI सुबह 8 बजे बेहद ख़राब श्रेणी में 300 से ज्यादा रहा. वहीं सिर्फ 4 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन दिल्ली कैंट, इग्नू, मैदान गढ़ी और अरबिंदो मार्ग पर AQI खराब श्रेणी में 250 के पार दर्ज हुआ था. सुबह 8 बजे दिल्ली का अक्षरधाम का इलाका गैस चैम्बर में तब्दील था. सिर्फ 50 मीटर विजिबिलिटी और अक्षरधाम मंदिर जहरीली धुंध की चादर में दिखायी तक नहीं दे रहा था.



शांति और उल्लास के साथ संपन्न हुई दीपावली, कहीं नहीं हुई अप्रिय घटना

एसपी रेखा यादव खुद मैदान में उतरीं, सादी वर्दी में तैनात रहे पुलिसकर्मी

महाकाली नदी पर एसएसबी, नेपाल पुलिस और जिला पुलिस ने साथ मनाई दीपावली



के.के.पी संवाददाता

चम्पावत। जिले में दीपावली का पर्व परंपरागत उल्लास और शांति के साथ संपन्न हो गया। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने स्वयं मैदान में उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने हर स्तर पर पहुंचकर पुलिसकर्मियों के साथ आमजन का भी मनोबल बढ़ाया। उनका संकल्प था कि दीपावली का त्योहार बिना किसी घटना-दुर्घटना के संपन्न हो, और पूरे जिले में कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।

पुलिस अधीक्षक ने त्योहार से पहले ही पुलिसकर्मियों के साथ अलग-अलग बैठकें कर निर्देश दिए थे कि इस बार दीपावली को शांतिपूर्ण और परंपरागत ढंग से संपन्न कराने के लिए ऐसा स्वस्थ माहौल तैयार किया जाए, जिसमें आम नागरिक बेखौफ होकर अपनी खुशियां मना सकें। इसी के तहत हर जगह पुलिस तैनात की गई और सादी वर्दी में पुलिसकर्मी हर स्थिति पर नजर रखे रहे।

एसपी के निर्देश पर भारत-नेपाल सीमा को बांटने वाली महाकाली नदी पर सुरक्षा में तैनात सशस्त्र सीमा बल, नेपाल पुलिस और जिला पुलिस के जवानों ने मिलकर दीपावली मनाई। इस दौरान सीमा पर सुरक्षा प्रबंधन को और मजबूत करने पर भी आपस में चर्चा हुई। पर्व शांतिपूर्वक निपटने पर एसपी ने सभी को बधाई दी और सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बेहतर सहयोग व समन्वय से मॉडल जिले चम्पावत को प्रदेश में बेहतर पुलिसिंग का उदाहरण बनाना है। राज्य स्थापना दिवस पर राज्य निर्माण के लिए त्याग और बलिदान देने वालों के प्रति कृतज्ञता जताते हुए उन्होंने कहा कि हम सबका कर्तव्य है कि उत्तराखंड को देश का समृद्ध, वैभवशाली और अपराधमुक्त राज्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं।

एसपी ने पुलिसकर्मियों को उनकी कर्तव्यनिष्ठा के लिए बधाई देते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि जिले की पुलिस जनता की हर कसौटी पर खरी उतर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस और आम जनता एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों के बीच का रिश्ता और मजबूत व भरोसेमंद होना चाहिए, जिसके लिए हर स्तर पर प्रयास जरूरी हैं, ताकि जिले को शांत रखते हुए हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

उत्तराखंड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर आंदोलनकारियों को नमन, उत्कृष्ट कार्य करने वाले सम्मानित

जिला सभागार में भव्य समारोह, विकास पुस्तिका का विमोचन, बाल वीरता पुरस्कार विजेता माया का विशेष सम्मान

डीएम ने विभागीय स्टॉलों का किया निरीक्षण, बोले – हर पात्र तक पहुंचे योजनाओं का लाभ



के.के.पी संवाददाता

चम्पावत। उत्तराखंड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर जिला सभागार में भव्य और गरिमामयी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के साहस को नमन किया गया और जिले के विकास व जनकल्याणकारी योजनाओं की झलक भी देखने को मिली।

कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी सहित जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। स्कूली छात्र-छात्राओं ने सरस्वती वंदना और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। इस दौरान सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की विकास पुस्तिका 'सशक्त नेतृत्व, विकास की ऊंची उड़ान' का विमोचन भी किया गया। राज्य आंदोलनकारी जिलाध्यक्ष बसंत सिंह तड़ागी, शंकर पांडे सहित वरिष्ठ आंदोलनकारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।

राज्य आंदोलनकारी श्याम नारायण पांडे और नवीन मुरारी ने आंदोलन के संघर्ष भरे दिनों को याद करते हुए कहा कि युवाओं ने बिना स्वार्थ के अलग राज्य के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी। यह राज्य बलिदानों की नींव पर खड़ा है, इसलिए इसकी अस्मिता और विकास की रक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है।

जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी ने कहा कि आज का उत्तराखंड आंदोलनकारियों के संघर्ष का प्रतिफल है। उन्होंने सभी को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं।

समारोह में जिलाधिकारी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। कृषि में नवाचार करने वाले 5 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया।

राज्य स्थापना दिवस पर नागरिकों ने ली लोकतंत्र की शपथ, निष्पक्ष मतदान का संकल्प

स्वीप कार्यक्रम के तहत डीएम मनीष कुमार ने दिलाई मतदाता शपथ, शत-प्रतिशत मतदान पर जोर



के.के.पी संवाददाता

चम्पावत। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सोमवार को जिला सभागार में आयोजित स्वीप जागरूकता कार्यक्रम में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने उपस्थित लोगों को मतदाता शपथ दिलाई। कार्यक्रम में लोकतंत्र के महापर्व में हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

सभी नागरिकों ने एक स्वर में शपथ ली कि वे भारत के लोकतंत्र में पूर्ण आस्था रखते हुए देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। साथ ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को कायम रखते हुए बिना किसी प्रलोभन या भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला प्रशासन के इस जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी चुनावों में शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करना और लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा।

उत्तराखंड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ जनपद बागेश्वर में हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मनाई गई





के.के.पी संवाददाता

बागेश्वर। उत्तराखंड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ जनपद बागेश्वर में हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कोतवाली स्थित शहीद स्मारक परिसर में जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे एवं पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा ने पुष्पांजलि अर्पित कर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी तथा उनके त्याग और बलिदान को नमन किया।

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रातः एनसीसी एवं एनएसएस के छात्र-छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में शामिल विद्यार्थियों ने 'हमारा उत्तराखण्ड कैसा हो, शहीदों के सपनों जैसा हो ', 'हमें चाहिए कैसा उत्तराखण्ड, शिक्षित उत्तराखण्ड, समृद्ध उत्तराखण्ड' तथा 'सारी धरती सारा अंबर, हमको प्यारा नौ नवंबर' जैसे नारों के उद्घोष के साथ राज्य आंदोलन के शहीदों को भावपूर्ण स्मरण किया। इसके उपरांत खेल विभाग द्वारा क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया।

नुमाइशखेत मैदान में आयोजित सम्मान समारोह का शुभारंभ जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे एवं विधायक पार्वती दास ने किया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। आंदोलनकारियों ने अपने संघर्ष के अनुभव साझा करते हुए राज्य के समग्र विकास, जनसमस्याओं के समाधान एवं बेहतर भविष्य के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी रखे।

इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। लोकगीतों एवं लोकनृत्यों के माध्यम से उत्तराखंड की समृद्ध लोकसंस्कृति और परंपराओं की सुंदर झलक देखने को मिली। साथ ही सूचना विभाग द्वारा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया, जिसमें राज्य में संचालित विकास कार्यों, उपलब्धियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी संकलित की गई है।

नुमाइशखेत मैदान में विभिन्न विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विभागीय सेवाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्टॉलों के माध्यम से आमजन को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, उनकी पात्रता एवं लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। बड़ी संख्या में लोगों ने स्टॉलों का भ्रमण कर योजनाओं की जानकारी प्राप्त की तथा विभिन्न विभागीय सेवाओं एवं योजनाओं का मौके पर ही लाभ उठाया।

राज्य आंदोलनकारी स्व. किशोरी लाल वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर किया नमन, आश्रितों की लंबित पेंशन व एरियर भुगतान की उठाई मांग



के.के.पी संवाददाता

अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारी स्वर्गीय किशोरी लाल वर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर 'विरासत हमर परिवार' की ओर से उनके आवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा दीप प्रज्वलित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। साथ ही उनके सुपुत्र भुवन वर्मा का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया और मिष्ठान भेंट कर राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण लंबे संघर्ष, त्याग और अनेक आंदोलनकारियों के बलिदान का परिणाम है। स्वर्गीय किशोरी लाल वर्मा ने राज्य आंदोलन के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और आंदोलन के समर्थन में जेल की यातनाएं भी सहीं। ऐसे आंदोलनकारियों के संघर्ष और समर्पण को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज पृथक उत्तराखंड राज्य के रूप में हमारी पहचान उन्हीं के संघर्षों की देन है। स्वर्गीय किशोरी लाल वर्मा के सुपुत्र भुवन वर्मा ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि यह उन आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को स्मरण करने का दिन भी है, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपील की कि वह राज्य आंदोलन के इतिहास को जाने, आंदोलनकारियों के योगदान को समझे और उनके संघर्षों को अपनी स्मृतियों में जीवित रखे। उन्होंने कहा कि जिस राज्य की पहचान और अस्तित्व के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, उसकी संस्कृति, परंपराओं और अस्मिता को सुरक्षित रखना आज के युवाओं की जिम्मेदारी है।

'विरासत हमर परिवार' के संयोजक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके पिता स्वर्गीय मोहन चंद्र गुरुरानी भी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। ऐसे में राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और उनके परिवारों की भावनाओं से उनका गहरा जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आंदोलनकारियों को उचित सम्मान मिलना चाहिए। उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए राज्य सरकार से मांग की गई कि प्रमुख राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थानों, सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों का नामकरण किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान और संघर्ष से प्रेरणा ले सकें।

बम पटाखे के हादशे से पांच लोग बच गए अपनी नेत्र ज्योति खोने से



के.के.पी संवाददाता

लोहाघाट /चंपावत। ज्योति पर्व दीपावली का त्यौहार जितना खुशनुमा होता है, उतना ही थोड़ी सी लापरवाही बरतने पर रंग में भंग होने में भी देर नहीं लगती है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विराज राठी द्वारा लोगों को पहले से ही आगाह किए जाने के बावजूद भी पांच ऐसे लोग अपनी नेत्र ज्योति बचाने से बच गए।यदि डॉक्टर राठी दीपावली अवकाश में घर गए होते तो उनका स्थानीय स्तर पर उपचार संभव ही नहीं था।जिला चिकित्सालय में भी विशेषज्ञ डॉक्टर अवकाश पर गए हुए थे। वहां से भी इसी प्रकार के हादसे के शिकार लोग उपचार के लिए लोहाघाट आए थे। डॉ, राठी ने पटाखे के बारूद से झुलसे पांच लोगों का बारीकी के साथ उपचार करते हुए उनके नेत्र ज्योति बचाने में सफलता प्राप्त की है। मालूम हो कि डॉक्टर राठी इससे पूर्व आंख के कई जटिल मामलों का उपचार कर लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान कर उन्हें राहत पहुंचाते आ रहे हैं।

कुमाऊनी लेखन पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा, सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बैठक

के.के.पी संवाददाता

अल्मोड़ा। राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन आयोजन समिति की बैठक सोमवार को नगर के एक होटल में आयोजित की गई। बैठक में सम्मेलन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और आयोजन से जुड़ी विभिन्न जिम्मेदारियां न्यास के सदस्यों को सौंपी गईं। बैठक में बताया गया कि सम्मेलन में करीब 30 वर्षों से कुमाऊनी भाषा के क्षेत्र में सक्रिय रचनाकार और भाषा प्रेमी भाग ले रहे हैं। यह सम्मेलन कुमाऊनी भाषा की चुनौतियों को सामने लाने के साथ ही भाषा के रचनाकारों को एक मंच प्रदान करेगा। बैठक में न्यास द्वारा कुमाऊनी भाषा में संचालित सात वार्षिक लेखन पुरस्कार योजनाओं के विजेताओं की भी घोषणा की गई। कुसुम कुसुम पठानी स्मृति बाल कहानी लेखन पुरस्कार के लिए डॉ. पवनेश ठकुराठी, डॉ. कुंदन रावत और दीपा पांडे, तारा जोशी स्मृति लेखन पुरस्कार के लिए कृतिका बिष्ट, ममता बिष्ट और सपना बिष्ट का चयन किया गया। भारतेंदु निर्मल जोशी स्मृति कुमाऊनी समालोचना लेखन पुरस्कार डॉ. गीता खोलिया, सुमन बुधलाकोटी और डॉ. हेम चंद्र दुबे को दिया जाएगा। जमुनादेवी खनी स्मृति कुमाऊनी संस्मरण लेखन पुरस्कार के लिए शिवदत्त पांडे, जनार्दन चिलकोटी और विनोद पंत का चयन हुआ है। इसी तरह शंकर लाल साह कुमाऊनी निबंध लेखन पुरस्कार शिवदत्त पांडे, मुन्नी पांडे और डॉ. राजीव जोशी को, अरुण कुमार भट्ट स्मृति कुमाऊनी यात्रा वृत्तांत लेखन पुरस्कार आनंद सिंह बिष्ट, डॉ. अर्चना जोशी और गिरीश चंद्र जोशी को तथा बचुली देवी स्मृति बाल कविता लेखन पुरस्कार राजेश्वरी पांडे, डॉ. कुंदन रावत और मीनू जोशी को प्रदान किया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक बागेश्वर के निर्देश पर फायर ब्रिगेड अलर्ट मोड पर: चण्डिका मंदिर के पास जंगल में लगी आग पर त्वरित कार्रवाई से पाया काबू

के.के.पी संवाददाता

दीपावली त्योहार के दृष्टिगत जनपद में सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद किया गया है। पुलिस अधीक्षक बागेश्वर जितेंद्र मेहरा (IPS) के निर्देशानुसार किसी भी संभावित अग्नि दुर्घटना से निपटने और जन-धन की सुरक्षा के लिए फायर ब्रिगेड को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिसके क्रम में कल दिनांक-08/11/2026 की रात्रि फायर स्टेशन बागेश्वर को चण्डिका मंदिर के पास के जंगल में अचानक आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। धार्मिक स्थल के समीप आग लगने की संवेदनशीलता और त्योहार के मद्देनजर विभाग तुरंत एक्शन मोड में आ गया। सूचना मिलते ही प्रभारी अग्निशमन अधिकारी दिनेश चंद्र पाठक के कुशल नेतृत्व में फायर यूनिट तत्काल मौके पर पहुंची फायर कर्मियों ने त्वरित सूझबूझ का परिचय देते हुए वॉटर टेंडर वाहन से पानी को पंपिंग कर हौज पाइप की सहायता से चण्डिका मंदिर स्थित झाड़ियों में लगी आग पर पानी डालना शुरू किया। फायर टीम की मुस्तैदी और कड़ी मशक्कत के चलते आग को अन्यत्र फैलने से रोक दिया गया और इसे पूर्ण रूप से बुझाकर शांत किया गया। इस त्वरित कार्रवाई के कारण एक बड़ा हादसा टल गया और घटना में अन्य कोई नुकसान नहीं हुआ है। कार्य समाप्ति के बाद फायर टीम वापस फायर स्टेशन उपस्थित हुई।

अग्निशमन टीम का विवरण:

1-प्रभारी अग्निशमन अधिकारी दिनेश चंद्र पाठक

2- DVR जगदीश सिंह,

3- FM अनिकेत सिंह,

4-FWअंजना,

5-FWदिव्या,

6-FWकाजल,

7-FWलोकेश

26वें राज्योत्सव पर राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान, विकास पुस्तिका 'सशक्त नेतृत्व, विकास की ऊँची उड़ान' का हुआ विमोचन



के.के.पी संवाददाता

अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 26वें राज्योत्सव के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मल्ला महल में आयोजित मुख्य समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच राज्य निर्माण में आंदोलनकारियों के योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें फूलमाला पहनाकर तथा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सूचना विभाग द्वारा प्रदेश के विकास कार्यों पर आधारित विकास पुस्तिका 'सशक्त नेतृत्व, विकास की ऊँची उड़ान' का विमोचन किया गया तथा उपस्थित लोगों को पुस्तिका वितरित की गई।समारोह में वक्ताओं एवं राज्य आंदोलनकारियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़ी स्मृतियों और अनुभवों को साझा किया। इस दौरान राज्य निर्माण के लिए किए गए संघर्ष और शहीदों के बलिदान को याद किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह को उत्सवमय बनाया।इससे पूर्व प्रातः विद्यालयों के बच्चों ने प्रभातफेरी निकालकर राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत की। जनरल बी. सी. जोशी शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। जिला मुख्यालय के साथ ही जनपद की सभी तहसीलों में भी राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित कर राज्य निर्माण में उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। मल्ला महल में आयोजित समारोह में मेयर अजय वर्मा, जिलाधिकारी अंशुल सिंह, दर्जा राज्य मंत्री कुंदन सिंह लटवाल एवं गोविंद पिल्खवाल, पूर्व विधायक कैलाश शर्मा एवं रघुनाथ सिंह चौहान, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक, केवल सती, महेश परिहार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति, राज्य आंदोलनकारी एवं आमजन उपस्थित रहे।

नेपाल सीमा से लगे गांवों में बगवाल महोत्सव का रंग, भक्ति में डूबे एक दर्जन गांव

महालक्ष्मी पूजन की रात गिरगढ़ में खेला गया पारंपरिक खेल, बलि की जगह अब श्रीफल से निभाई जा रही रस्म

प्रवासी भी पहुंचे गांव, भैया दूज पर निकलेगी मां भगवती की भव्य शोभायात्रा



के.के.पी संवाददाता

लोहाघाट। नेपाल सीमा से लगे गांवों में बगवाल महोत्सव शुरू हो गया है। एक दर्जन से अधिक गांवों में खूब चहल-पहल है और लोग भक्तिभाव में डूबे हुए हैं। महोत्सव में शामिल होने के लिए विभिन्न स्थानों से प्रवासी अपने गांवों का रुख कर चुके हैं और कई लोग पहुंच भी गए हैं।

महालक्ष्मी पूजन की रात गिरगढ़ में पारंपरिक खेल खेला गया। पहले यहां कटरे (भैंस के बच्चे) की बलि देकर उसके सिर से गेंद बनाकर यह खेल खेला जाता था, लेकिन अब यह परंपरा समाप्त हो चुकी है और श्रीफल से इसकी रस्में निभाई जा रही हैं।

एक दर्जन गांवों के लोगों ने जत्थों के साथ पहुंचकर मंदिर की परिक्रमा की। पुरुषों ने द्युस्के गाए, जबकि महिलाओं ने झोड़ा गायन कर मां भगवती के जयकारे लगाए। परिक्रमा के बाद मां भगवती, कैलपाल, छलेवाड़ी और रौल देवता के अवतरित डांगरों ने सभी को आशीर्वाद दिया। इसी दिन मझपीपल और बगोटी के लिए युवा बाजे-गाजों के साथ भगवती मंदिर की ओर रवाना हुए।

ग्राम प्रधान महेश जोशी, महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष आनंद जोशी, संतोक धौनी, दयाकृष्ण उपाध्याय, प्रवीण पांडे, शेखर पांडे और भुवन भट्ट सहित अनेक लोग आयोजन को भव्य बनाने में जुटे हैं। भैया दूज के दिन भगवती मंदिर मझपीपल और बूंगा से मां भगवती की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस पर शहीद स्मारक पहुंचकर राज्य आंदोलन के अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

के.के.पी संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कचहरी परिसर, देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर राज्य आंदोलन के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने पृथक उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन करते हुए उनके संघर्ष और बलिदान का स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम है। राज्य आंदोलन में मातृशक्ति, युवाओं, छात्रों, पूर्व सैनिकों सहित समाज के सभी वर्गों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभी के सामूहिक संघर्ष और संकल्प से पृथक उत्तराखण्ड राज्य का सपना





साकार हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण कर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। इन वर्षों में प्रदेश ने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए विकास के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तराखण्ड को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों तक विकास का लाभ पहुंचाने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और पलायन रोकना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस हमें अपने गौरवशाली संघर्ष और बलिदान को स्मरण करने के साथ ही विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण के संकल्प को और मजबूत करने की प्रेरणा देता है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल पहचान को संरक्षित रखते हुए उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि शहीद आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखण्ड का निर्माण ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

राज्य स्थापना दिवस पर पिथौरागढ़ में विविध कार्यक्रम आयोजित, राज्य आंदोलनकारियों के त्याग एवं बलिदान को किया नमन

विकास पुस्तिका का हुआ विमोचन, राज्य आंदोलनकारियों को शॉल ओढ़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर किया सम्मानित

के.के.पी संवाददाता

पिथौरागढ़। उत्तराखंड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ जनपद पिथौरागढ़ में सादगीपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय स्थित रामलीला मैदान में आयोजित किया गया, जबकि जनपद के उपजिला मुख्यालयों में भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य स्थापना दिवस मनाया गया।

इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

रामलीला मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डीडीहाट विधायक श्री



बिशन सिंह चुफाल एवं जिलाधिकारी श्री आशीष कुमार भटगांई ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके उपरांत राज्य आंदोलनकारियों के चित्रों पर माल्यार्पण कर उनके संघर्ष, त्याग एवं बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया।

कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं एवं सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। लोकगीतों एवं लोकनृत्यों के माध्यम से उत्तराखंड की समृद्ध लोकसंस्कृति की आकर्षक झलक प्रस्तुत की गई।

इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों द्वारा सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की ओर से प्रकाशित राज्य की विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। साथ ही राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों को जिलाधिकारी एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा शॉल ओढ़ाकर तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस पर विकास पुस्तिका 'सशक्त नेतृत्व, विकास की ऊँची उड़ान' का किया विमोचन

विकास पुस्तिका प्रदेश की उपलब्धियों के साथ जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही का भी दस्तावेज : मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के निर्माण की दिशा में तेजी से हो रहा कार्य

विकास का वास्तविक अर्थ आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना : मुख्यमंत्री

के.के.पी संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज, गढ़ी कैंट, देहरादून में आयोजित समारोह में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की विकास पुस्तिका-2026 'सशक्त



नेतृत्व, विकास की ऊँची उड़ान' का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पुस्तिका प्रदेश की विकास यात्रा, जनकल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। विकास पुस्तिका जनता के सामने सरकार के कार्यों का हिसाब प्रस्तुत करने के साथ भविष्य की जिम्मेदारियों का भी स्मरण कराती है।

मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलन के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण जनता के लंबे संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। राज्य निर्माण में मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पृथक उत्तराखण्ड राज्य का सपना साकार हुआ। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य को समृद्ध और विकसित बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का वास्तविक अर्थ केवल योजनाओं और आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका सकारात्मक प्रभाव आम नागरिकों के जीवन में दिखाई देना चाहिए। किसी गांव तक सड़क पहुंचने से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, विद्यालयों में अच्छी सुविधाएं मिलने से बच्चों के सपनों को नई उड़ान मिलती है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने से पलायन की समस्या का समाधान होता है।

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर महानगर कांग्रेस ने मनाई वर्षगांठ, केक काटकर दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ

के.के.पी संवाददाता

हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक सुमित हृदयेश एवं महानगर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट सहित कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्य स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केक काटकर एक-दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी गईं। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण यहां की जनता के लंबे संघर्ष, आंदोलनकारियों के त्याग और शहीदों के बलिदान का परिणाम है। राज्य निर्माण की मूल भावना पहाड़, मैदान और यहां के प्रत्येक नागरिक के विकास, सम्मान, रोजगार और बेहतर



भविष्य से जुड़ी हुई थी। आज आवश्यकता है कि हम सभी मिलकर उन सपनों का उत्तराखंड बनाने का संकल्प लें, जिसके लिए हमारे आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया था। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट और जिला अध्यक्ष राहुल छिमवल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि राज्य आंदोलन के शहीदों और आंदोलनकारियों के त्याग एवं बलिदान को याद करने का दिन भी है। आज हमें आत्ममंथन करना चाहिए कि जिन उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, वे कितनी पूरी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की अस्मिता, जनता के अधिकारों और प्रदेश के विकास के लिए सदैव संघर्षरत रही है और आगे भी जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी।

कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित कांग्रेसजनों ने उत्तराखंड के उज्ज्वल भविष्य, खुशहाली और समग्र विकास की कामना करते हुए प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। विधायक सुमित हृदेश महानगर अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट जिला अध्यक्ष राहुल छिमवल हरिश मेहता हेमंत बगड़वाल मलय बिष्ट अमित रावत हेमंत साहू महेश आनंद स्द्धड्डठ्ठद्मड्डह्व चश्रद्धद्यद्व ब्लॉक अध्यक्ष किरण माहरा जाकिर हुसैन हाजी सुहेल सिद्दीकी जया कर्नाटक देवेंद्र मेहर गोविंद बगड़वाल बबलू बिष्ट हाजी शाद अली गणेश टम्टा उदित करायत मंजू दानू ताहिर भाई संदीप भैंसोड़ा मनोज भट्टआदि उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजा शुभकामना संदेश, उत्तराखंड की विकास यात्रा और उपलब्धियों की सराहना की

21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक के संकल्प को राज्य सरकार साकार कर रही है : प्रधानमंत्री

विकसित उत्तराखंड से विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है प्रदेश : प्रधानमंत्री

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का जताया आभार, कहा- उनके मार्गदर्शन और सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है

के.के.पी संवाददाता

देहरादून। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर उत्तराखंड के समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने विस्तृत संदेश में उत्तराखंड की 26 वर्षों की विकास यात्रा, राज्य की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत, आधारभूत ढांचे के विस्तार, सीमांत क्षेत्रों के विकास तथा विभिन्न क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 9 नवंबर 2000 को भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प से उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। राज्य स्थापना की यह वर्षगांठ देवभूमि के लोगों के अदम्य साहस, अटूट स्वाभिमान और अनवरत प्रगति के संकल्प को नमन करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के समय जिन आकांक्षाओं के साथ उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, आज प्रदेश उन्हें साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा यह प्रदेश प्रकृति के अनुपम सौंदर्य और आध्यात्मिक वैभव का संगम है। मां गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का उद्गम इसी धरती से होता है। पंच केदार, पंच प्रयाग और चारधाम की परंपरा उत्तराखंड को देश की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। बाबा केदारनाथ और बदरीविशाल से लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, जागेश्वर धाम और आदि कैलाश तक प्रदेश के पवित्र स्थल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़े हैं। उन्होंने उत्तराखंड से अपने पुराने जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि संगठन के कार्यों के दौरान उन्होंने देवभूमि के अनेक क्षेत्रों में लंबा समय बिताया है। केदारनाथ की दिव्य गुफा में साधना, आदि कैलाश की आध्यात्मिक यात्रा, बुग्यालों का आशीर्वाद और माताओं-बहनों का स्नेह आज भी उनकी स्मृतियों में जीवंत है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की पूरी क्षमता वाला प्रदेश बताते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे के विस्तार की सराहना

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'विकसित उत्तराखंड से विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने के लिए पिछले एक दशक में राज्य की कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे का व्यापक विस्तार हुआ है। केंद्र सरकार ने लगभग 890 किलोमीटर लंबी चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना पर 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। लगभग 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना पर भी कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये परियोजनाएं चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के साथ ही प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को उत्तराखंड के पर्यटन, व्यापार और उद्योगों के लिए नई क्रांति बताते हुए कहा कि इससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय काफी कम होगा। देहरादून एयरपोर्ट का विस्तार, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का संचालन, बनबसा में नए हेलीपैड की स्वीकृति तथा हेलिपोर्ट और हेलिपैड नेटवर्क का विस्तार राज्य में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है।

धार्मिक एवं सीमांत क्षेत्रों के विकास को बताया महत्वपूर्ण

प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण को विशेष महत्व का कार्य बताते हुए कहा कि धाम के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये के कार्य किए गए हैं। बदरीनाथ धाम में भी लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से रिवर फ्रंट, प्लाजा और मास्टर प्लान के तहत विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में उत्तराखंड की दिव्यता, भव्यता और पर्यावरण को प्राथमिकता दी गई है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने वाले 02 आरोपी पुलिस ने दबोचे

सोशल मीडिया पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर वीडियो वायरल करने के मामले में सिडकुल पुलिस की कार्रवाई

थाना सिडकुल में मुकदमा अपराध संख्या 474/26 के तहत IT एक्ट, BNS एवं SC/ST एक्ट में दर्ज था मुकदमा

पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत मे लिया अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

के.के.पी संवाददाता

सिडकुल। दिनांक 02.11.2026 को थाना सिडकुल क्षेत्रांतर्गत रोशनाबाद में कुछ व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किए जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी।

शिकायत के आधार पर थाना सिडकुल में मुकदमा अपराध संख्या 474/26, धारा 67 IT Act, 351(2) BNS एवं धारा 3(1)(द) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार



निवारण) अधिनियम के अंतर्गत वंशपाल आदि के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

मामले में कार्रवाई करते हुए दिनांक 09.11.2026 को पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को हिरासत मे लिया। आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

नाम पता आरोपित

1. दीपांशु पाल पुत्र राजीव पाल, निवासी ग्राम रोशनाबाद, थाना सिडकुल, जनपद हरिद्वार उम्र 19 वर्ष

2. वंशपाल पुत्र प्रवीन पाल, निवासी ग्राम रोशनाबाद, थाना सिडकुल, जनपद हरिद्वार उम्र 19 वर्ष

पुलिस टीम

1. उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान

2. हेड कांस्टेबल कुलदीप बगासी

3. कांस्टेबल मनीष

डॉ.अनिल दीक्षित द्वारा रचित, माया देवी विश्वविद्यालय के 'कुलगीत' का भव्य लोकार्पण

के.के.पी संवाददाता

देहरादून। माया देवी यूनिवर्सिटी के 'कुलगीत' का दीपोत्सव पर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट श्री मनोहर लाल जुयाल द्वारा भव्य लोकार्पण स्क्रीनिंग के जरिये किया गया, जिसकी रचना स्कुल ऑफ़ लॉ एन्ड लीगल स्टडीज़ के डीन प्रो.(डॉ.)अनिल कुमार दीक्षित ने की है

माया देवी यूनिवर्सिटी के इस 'कुलगीत' को सुर ओर संगीत से सज़ाया है श्री रोहन दीक्षित ने जिसमे विश्वविद्यालय के विजन, मिशन और कोर-वैल्यूज को सुरीले अंदाज़ में लयबद्ध किया गया है, यूनिवर्सिटी के सभागार में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम को इतिहासिक बनाते हुए सभी वरिष्ठ प्रोफेसरगण, संकायअध्यक्ष, रजिस्ट्रार, परीक्षा-नियंत्रक एवं विभिन्न संस्थानो के शिक्षकों की



मौजूदगी में कुलगीत का गायन हुआ एवं इसे विश्वविद्यालय को समर्पित किया गया। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट प्रो.(डॉ.) तृप्ति जुयाल सेमवाल ने कुलगीत के आत्मबोध का परिचय सभागार में मौजूद सभी शिक्षकों को कराते हुए कहा कि आज का ये ऐतिहासिक पल हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करेगा

विश्वविद्यालय के कुलसाचिव प्रो.(डॉ.) आशीस सेमवाल ने कुलगीत की विषय वस्तु पर चर्चा की एवं यूनिवर्सिटी क़ी स्थापना के समय से लेकर आज तक क़ी संकल्प यात्रा का वर्णन किया, इस अवसर पर माया देवी एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती प्रभा जुयाल ज़ी ने सभी को अपना आशीर्वचन प्रदान किया

लोकार्पण कार्यक्रम के समापन पर स्कूल ऑफ़ लॉ एन्ड लीगल स्टडीज़ के डीन प्रो.(डॉ.)अनिल कुमार दीक्षित ने मौजूद सभी सम्मानित आगन्तुकों के प्रति आभार अर्पित किया।

राज्य बने 26 सालों बाद भी दूरस्थ विधानसभा भीमताल को नहीं मिल पाया अपना बड़ा हॉस्पिटल

के.के.पी संवाददाता

भीमताल। समाजसेवी बृजवासी ने माँग को दोहराते हुए राज्य सरकार से भीमताल विधानसभा को मानवीय एवं पर्यटन दृष्टिकोण से 'दो सौ' बेड का बड़ा अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हॉस्पिटल शीघ्र देने को कहा भीमताल उत्तरखंड राज्य की 57 वीं विधानसभा है जिसके अंतर्गत दूरस्थ ब्लाक ओखलकाण्डा, धारी, रामगढ़ और भीमताल को मिलाकर चार ब्लाक आते हैं जिसमें लगभग 70% किसान परिवार निवासी हैं द्य इसके अलावा भीमताल विधानसभा पर्यटन क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखती है द्य स्वास्थ्य सेवाओं की बात करे तो आज राज्य बने 26 सालों के बाद भी भीमताल विधानसभा के इतने बड़े भू-भाग को 200 बेड वाले अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से परिपूर्ण बड़ा अस्पताल न मिल सका, जिसके कारण दूरस्थ ब्लाकों के मरीजों का दम रेफर के दौरान बीच रास्तो पर ही घुट जाता है द्य यह एक बड़ी विडंबना है, समस्त भीमताल विधानसभा वासी के आजादी के इतने सालों बाद भी एक बड़े हॉस्पिटल से वंचित है, जिसके कारण एक्सिडेंटल, गर्भवती महिला उपचार के केशों पर मरीज एवं उनके परिवार जनों को भारी क्षति पहुंचती हैं द्य भीमताल विधानसभा सामाजिक कार्यकर्ता पूरन चंद्र बृजवासी ने राज्य सरकार से भीमताल विधानसभा के अंतर्गत चारों ब्लाकों के सेंटर जोन पर जमीन चयनित कर एक बड़े 200 बेड वाले अस्पताल का



निर्माण कराने की मांग की है द्य ताकि विधानसभा अंतर्गत की जनता को इसका सीधा लाभ मिल पाए। बेरोजगार संघः राज्य के निर्माण हुए 26 साल बाद भी कुमाऊं द्वार 'पर्यटन नगरी' भीमताल को नहीं मिल सका अपना 'रोड वेज बस अड्डा', नगरवासी उत्तर प्रदेश सरकार के समय से अब तक लगाए बैठे हैं आश

सामाजिक कार्यकर्ता पूरन चंद्र बृजवासी अब तक कई बार परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री सहित राज्य के कई माननीयों को दे चुके हैं ज्ञापन

राज्य सरकार को शीघ्र नगर क्षेत्र भीमताल में रोडवेज बस स्टेशन निर्माण कार्य की शुरुआत कराने के लिए समाजसेवी बृजवासी ने कहा कि भीमताल कुमाऊं द्वार आज दिनों-दिन पर्यटन नगरी में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है साथ ही भीमताल शिक्षण संस्थानों के 'हब' के रूप में भी अपनी विशेष पहचान बना रहा है, यहाँ कई हजारों की संख्या में अन्य राज्यों के बच्चे आकर शिक्षा लेते हैं इसके अलावा भीमताल अपने आस-पास पैराग्लाइडिंग हब, वॉटर स्पोर्ट्स हब, अडवेंचर हब और अन्य कई पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक स्थलों को अपने साथ जोड़ हुआ है, हर वर्ष कई लाखों की संख्या में पर्यटक देश-विदेश से भीमताल पहुँचते है और यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का लुफ्त उठाते हैं लेकिन 'अथिति देवो भवः' की परम्परा निभाने वाले पर्यटन नगरी भीमताल के वासींदा पर्यटकों के रोड वेज बस स्टैंड इधर-किधर है पूछने पर हर बार शर्मिंदगी उठाते हैं जबकि उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व 'उत्तर प्रदेश सरकार' ने भीमताल डाठ पर कुमाऊं द्वार नगर भीमताल वासियों के लिए रोडवेज का टिकट काउंटर बनाया था और लोगों को स्टैंड की सुविधा दी थी जो राज्य बनने के समय से हटा दी गयी, तब से अब तक न जानें भीमताल वासियों ने कितनी बार शासन-प्रशासन से भीमताल में रोडवेज बस स्टैंड खुलवाने की मांग की है, आज भीमताल नगर परिसीमन के उपरांत लगभग अपने 'भौगोलिक क्षेत्र' में 14.57 वर्ग किमी. की बढ़ोत्तरी कर चुका है साथ ही भीमताल नगर के एक छोर सातताल से दूसरी छोर नौकुचियाताल तक पर्यटन फैल चुका है, जानकारी के मुताबिक नगर की जनसंख्या करीब 18000 से भी पार हो चुकी है किन्तु नगर वासियों को इतने बड़े भू-भाग में एक छोटा सा रोडवेज का बस अड्डा अब तक नसीब नहीं हुआ, आज भी यात्री-यात्रा के लिए घंटो 'धूप व बरसात' में रोड किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करते हैं, भीमताल विधानसभा क्षेत्र के समाजसेवी पूरन चंद्र बृजवासी ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शासन-प्रशासन दोनों के प्रतिनिधियों से बारी-बारी से भीमताल में रोड वेज बस अड्डा खुलवाने की माँग रखी गयी लेकिन जमीन का चयन न होने का हवाला देकर भीमताल की मुख्य माँग को अब तक अनदेखा किया गया है जिसका परिणाम पूरे नगर को प्रत्यक्ष भुगतना पड़ रहा है साथ ही उन्होंने बताया कि एक पत्र के जवाब में 'परिवहन विभाग' खुद कह चुका है कि भीमताल में रोड वेज बस स्टैंड की माँग 'नीतिगत विषय' है, साथ में जिला प्रशासन पहले जमीन न होने की बात कहता था, किन्तु बाद में जमीन का चयन किए जाने का जिक्र भी करता है, दर्जनों पत्रों का पत्राचार करने के उपरांत 2 बार परिवहन सचिव ने क्षेत्र का दौरा किया, किंतु स्थापना निर्माण कार्यवाही की शुरुआत तक नहीं हुई, समाजसेवी बृजवासी ने पुनः राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शीघ्र धरातल पर रोडवेज बस स्टेशन निर्माण कार्य की शुरुआत कराने को कहाँ, आशा है मुख्यमंत्री धामी के दिशा-निर्देश पर राज्य सरकार शीघ्र ही भीमताल में रोड वेज बस अड्डा खोलने पर काम करेगी।

संपादकीय

भारत-पाक राजनीतिक संबंध सुधारने का आ गया समय?

दुनियां के प्रमुख शक्तिशाली देशों में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रमों ने विकासशील देशों के लिए चेतावनी देने का काम किया है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यावधि चुनाव में करारी हार को लेकर चर्चाएं आम हैं वहीं दूसरी तरफ इजरायल में नेतन्याहू को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से साफ संदेश दुनिया को मिला है कि आमजनता हिंसा और युद्ध में विश्वास नहीं करती है। इससे पहले बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों की सरकारों को तो युवाओं ने ही आंदोलन के जरिये बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मतलब साफ है सभी देशों के नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ ही देश में सुख-शांतिपूर्ण वाला विकास चाहिए। भौगोलिक सीमाओं से परे सभी शांति चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ऐसा करने में बैरियर्स बनती हैं। भारत और पाकिस्तान का ही उदाहरण ले लें। दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव और उसके परिणामस्वरूप पैदा हुई आर्थिक मुश्किलों की दो तस्वीरें इन दिनों सामने हैं। पाकिस्तान की ओर से अपना हवाई क्षेत्र बंद किए जाने के कारण एयर इंडिया के परिचालन पर पड़ रहे असर का हवाला देते हुए कंपनी के सीईओ टेवोल्डे नुकसान का हिसाब गिना रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान में पाक-भारत बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन नूर मोहम्मद कसूरी भारत के साथ व्यापार बंद होने से अपने देश को हुए करीब 40 अरब डॉलर के नुकसान का दावा करते हुए कारोबार बहाल करने की भावुक अपील कर रहे हैं। इन दोनों बयानों के बीच एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि आखिर दोनों देशों के बीच तनाव की कीमत कब तक आम लोगों, कारोबारियों और अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ेगी?

एयर इंडिया के सीईओ का कहना है कि पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंधों के कारण कंपनी को अपने उड़ान मार्गों और नेटवर्क की योजना बदलनी पड़ रही है। उनके मुताबिक, इस समस्या से कंपनी के प्रतिस्पर्धी विमानन समूह प्रभावित नहीं हैं। यानी एक ही क्षेत्र में कारोबार करने वाली कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियां भी समान नहीं रह गई हैं। इसके अलावा पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और ईंधन की कीमतों में पिछले साल के मुकाबले दोगुने से अधिक वृद्धि ने विमानन उद्योग की मुश्किलें बढ़ाई हैं। एयर इंडिया इसे अल्पकालिक चुनौती मानते हुए भविष्य में मजबूती से उभरने की बात कर रही है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं रहता। इसका बोझ अंततः परिचालन लागत, टिकट की कीमतों और यात्रियों पर भी पड़ सकता है। दूसरी तरफ, पाकिस्तान के कारोबारी जगत से उठ रही आवाज भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। नूर मोहम्मद कसूरी का दावा है कि भारत के साथ व्यापार बंद होने से पाकिस्तान को लगभग 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा और व्यापारिक संबंधों पर रोक लग गई। इसके बाद पाकिस्तान के कारोबारियों को कच्चे माल और जरूरी वस्तुओं के लिए दूरस्थ देशों का रुख करना पड़ा। ब्राजील, चीन, मिस्र और अमेरिका जैसे देशों से आयात करने के कारण परिवहन खर्च बढ़ा और आपूर्ति में अधिक समय लगने लगा। इसका सीधा असर उत्पादन लागत और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर पड़ा।

देश आख़िर कब जानेगा चीनी घुसपैठ का सच?

तनवीर जाफ़री

भारत और चीन के बीच लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात एल ए सी पर सीमा विवाद है। भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों और विभिन्न रक्षा व कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, चीन पर भारत के मुख्य रूप से पश्चिमी, मध्य और पूर्वी तीन सेक्टर्स में अवैध क़ब्ज़ा करने या बार-बार घुसपैठ करने के आरोप लगते रहे हैं। इनमें पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख क्षेत्र वर्तमान में सबसे अधिक संवेदनशील है, जहाँ चीन ने बड़े भूभाग पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है और लगातार घुसपैठ की कोशिशें करता रहता है। इसमें चीन जम्मू-कश्मीर/लद्दाख के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र यानी अक्साई चिन पर अवैध रूप से कब्ज़ा किए हुए है। पैंगोंग त्सो नामक 134 किलोमीटर लंबी झील के फ़िंगर एरिया 1 से 8 पर दोनों देशों की अलग-अलग धारणा है। जून 2020 के तनाव के दौरान चीनी सैनिकों पर फ़िंगर 4 तक भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने का आरोप लगा था। इसी तरह गलवान घाटी में जून 2020 में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। उस समय भी चीन पर इस रणनीतिक घाटी में अपनी स्थिति आगे बढ़ाने का आरोप लगा था।इसके अतिरिक्त इसी पश्चिमी सेक्टर के डेपसांग मैदानी इलाक़े में और डेमचोक क्षेत्रों में भी चीनी सेना द्वारा भारतीय गश्ती दलों को रोकने और एलएसी के निकट टेंट गाड़ने के आरोप समय-समय पर लगते रहे हैं।

इसके अलावा देश के पूर्वी सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम क्षेत्र में चीन की दावेदारी और घुसपैठ दोनों भारत के लिये गंभीर चिंता का विषय है। चीन तो पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत (जांगनान) कहता है और भारत के इस अभिन्न अंग पर अपना दावा ठोकता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में दिसंबर 2022 में यांगत्से के पास और हाल ही में तक्सिंग क्षेत्र के पास चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सीमा में घुसने के प्रयास किए गए, जिन्हें भारतीय सेना ने विफल कर दिया। जबकि स्थानीय विपक्ष और अनेक रिपोर्टों में चीन द्वारा कुछ किलोमीटर अंदर तक अस्थायी टेंट लगाने के आरोप भी लगाए गए हैं। चीन पर आरोप है कि उसने एलएसी के बेहद क़रीब या विवादित क्षेत्रों में मॉडल विलेज और सड़कें बना ली हैं। इसके जवाब में भारत ने भी हाल ही में चीन द्वारा दावा की जाने वाली 28 जगहों के नाम आधिकारिक तौर पर निर्धारित कर अपनी स्थिति मज़बूत की है।

सिक्किम सीमा पर स्थित नाकु ला दर्रे के पास भी चीनी सैनिकों द्वारा सीमा लांघने और भारतीय सेना के साथ आमने-सामने होने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

मध्य सेक्टर के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इलाक़ों के भारत चीन सीमा क्षेत्रों को तुलनात्मक रूप से शांत माना जाता है, लेकिन यहाँ भी चीनी घुसपैठ के आरोप लगते रहे हैं। मिसाल के तौर पर उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित बाराहोती चरागाह क्षेत्र में चीनी सैनिकों और नागरिकों द्वारा एलएसी पार कर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने और बुनियादी ढाँचे को नुक़सान पहुँचाने के आरोप कई बार लगे हैं। समय-समय पर चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा की यथास्थिति को बदलने और नए क्षेत्रों पर दावा ठोकने के आक्रामक प्रयास भी जारी रहते हैं। गत 22 अक्टूबर 2026 को राजस्थान के अलवर में आईटीबीपी के हिमवीर सम्मान समारोह के दौरान महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए यह स्वीकार भी किया कि अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई स्थानों पर चीनी सैनिकों के साथ आमने-सामने की स्थिति बनी हुई है और यह गतिरोध लगातार जारी है। उन्होंने एक व्यावहारिक और गंभीर सैन्य आकलन देते हुए यह भी कहा कि चीन ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण में भारी निवेश किया है। इसलिए, पारंपरिक तरीक़ों से सीधे तौर पर चीन का मुक़ाबला करना मुश्किल हो सकता है।

महानिदेशक शत्रुजीत सिंह अपने उपरोक्त बयान देने के कुछ ही दिनों बाद 31 अक्टूबर सेवानिवृत्त भी हो गए परन्तु उनके वक्तव्य से देश की घरेलू राजनीति में एक बड़ा सियासी संग्राम शुरू हो गया। विपक्ष ने सरकार से मांग की कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा, चीनी घुसपैठ की वास्तविक सीमा, और चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर संसद और देश के सामने स्थिति स्पष्ट करे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सीमा पर स्थिति गंभीर है जबकि सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही थी। चूंकि सीमा सुरक्षा से जुड़ा शत्रुजीत सिंह का यह बयान बेहद संवेदनशील था और इसने सुरक्षा से जुड़ी रणनीतिक सच्चाइयों को उजागर किया था, इसलिए विवाद बढ़ते ही आईटीबीपी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से शत्रुजीत सिंह के इस भाषण के वीडियो को हटा दिया गया । परन्तु वीडियो हटा लेने से अपनी कमज़ोरियाँ ख़त्म नहीं हो जातीं ?

एक बार इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी फ़रवरी 2023 में एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू के दौरान चीन को बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत को तुलनात्मक रूप से छोटी अर्थव्यवस्था बताते हुए व्यावहारिक कूटनीति की वकालत की थी। उस समय भी उनके इस बयान को लेकर विपक्षी दलों ने उन पर भारत की कमज़ोरी ज़ाहिर करने का आरोप लगाया और सोशल मीडिया पर इस पर काफ़ी बहस हुई थी। जयशंकर ने उस समय स्पष्ट शब्दों में कहा था कि -देखिए, वे (चीन) बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम एक छोटी अर्थव्यवस्था हैं। क्या मैं एक बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ जाकर लड़ाई मोल ले लूं? यह लड़ाई लड़ने की बात नहीं है, यह सामान्य समझ की बात है। विदेश मंत्री का तर्क था कि भारत और चीन के बीच आर्थिक अंतर एक हक़ीक़त है। उन्होंने कहा था कि एक समझदार और व्यावहारिक देश के रूप में भारत को अपनी सीमाओं और क्षमताओं को समझते हुए कूटनीति चलनी चाहिए, न कि बिना सोचे-समझे किसी बड़ी आर्थिक महाशक्ति से सीधे टकराव में पड़ना चाहिए।

ऐसे में सवाल यह है कि विदेश मंत्री जयशंकर और आई टी बी पी के पूर्व महानिदेशक शत्रुजीत सिंह की स्वीकारोक्ति अथवा स्पष्टवादिता या साफ़गोई के बीच स्वयं को मज़बूत बताने वाली सरकार व 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री मोदी से चीनी घुसपैठ का सच, आख़िर देश आख़िर कब जान सकेगा ?

जलवायु सम्मेलन से भारत की उम्मीदें और चुनौतियां

राज कुमार सिन्हा

जलवायु परिवर्तन आज पूरी मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह केवल पर्यावरण का सवाल नहीं, बल्कि मानव जीवन, खाद्य सुरक्षा, जल संसाधनों, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। तुर्की में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कोप -31 की शुरुआत कल 9 से 20 नवंबर के बीच अंताल्या शहर में प्रारंभ हो गया है। इस गंभीर वैश्विक चुनौती के बीच सम्मेलन से दुनिया को उम्मीद है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस और प्रभावी फैसले लिए जाएंगे। तुर्की को आधुनिक और पर्यावरण-सचेत देश के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। वह इस सम्मेलन का आधिकारिक मेजबान है। लेकिन सवाल यह है कि क्या टिकाऊ विकास और जलवायु परिवर्तन को कम करने की राह इतनी आसान होगी? क्या दुनिया के विकसित और विकासशील देश अपने आर्थिक हितों से ऊपर उठकर पृथ्वी के भविष्य के लिए साझा जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं?यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न देशों और क्षेत्रों को एक मंच पर लाकर बातचीत, सहयोग और निर्णय प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है।कोप -31 महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें वैश्विक जलवायु कार्यवाही को तेज करने, देशों की जवाबदेही सुनिश्चित करने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा पूरी दुनिया में जलवायु न्याय, जलवायु अनुकूलन और सतत विकास को आगे बढ़ाने पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।यह ऐसा सम्मेलन है जहां देशों को अपने जलवायु लक्ष्यों पर कठोर और ठोस निर्णय लेने होंगे। पेरिस समझौते (2015) के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि केवल वादों और घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके परिणाम जमीन पर दिखाई देने चाहिए।कार्बन उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। दुनिया ने वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का वादा किया था, लेकिन मौजूदा नीतियों और उत्सर्जन की गति के कारण विश्व 2.4 से 2.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। यह स्थिति पूरी दुनिया के लिए गंभीर चेतावनी है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस सम्मेलन में देशों पर नए और अधिक कठोर राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्य घोषित करने का दबाव बनेगा। कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने की स्पष्ट समय-सीमा तय करने की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण मुद्दा होगी। इसके साथ ही भारत, ब्राजील, अफ्रीकी देशों और छोटे द्वीपीय देशों जैसे विकासशील राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर भी गंभीर निर्णय लेने होंगे।भारत के लिए कोप -31 केवल एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नहीं है, बल्कि अपने पर्यावरणीय भविष्य और विकास की दिशा पर पुनर्विचार करने का अवसर भी है। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और उसकी ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। एक ओर देश औद्योगिक विकास, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव भी झेल रहा है।भारत में बढ़ती गर्मी, भीषण लू, अनियमित मानसून, कम समय में अत्यधिक बारिश, बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी घटनाएं जलवायु संकट की गंभीरता को उजागर कर रही है। हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों का पिघलना, नदियों के जल प्रवाह में बदलाव और समुद्र के बढ़ते जलस्तर से तटीय क्षेत्रों पर खतरा बढ़ रहा है। इसका सीधा असर कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और करोड़ों लोगों की आजीविका पर पड़ रहा है।भारत की बड़ी आबादी कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण समुदायों का जीवन जंगल, जमीन, नदियों और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण जंगलों में आग, जलस्रोतों का सूखना, जैव विविधता का नुकसान और खेती की उत्पादकता में गिरावट जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसलिए भारत की जलवायु नीति में इन समुदायों के पारंपरिक ज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।भारत ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्यवाही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। लेकिन दूसरी ओर कोयला आधारित बिजली उत्पादन और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता अभी भी एक बड़ी चुनौती है। विकास के नाम पर नए कोयला आधारित बिजली संयंत्रों, बड़े बांधों, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करते समय उनके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का गंभीर मूल्यांकन जरूरी है। केवल ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना ही विकास का पैमाना नहीं हो सकता। यह भी देखना होगा कि ऊर्जा उत्पादन की कीमत कौन चुका रहा है और उसका लाभ किसे मिल रहा है।भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में ऊर्जा नीति का आधार विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा होना चाहिए। गांवों, पंचायतों और स्थानीय समुदायों को सौर ऊर्जा उत्पादन से जोड़ना, कृषि में स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना, ऊर्जा भंडारण की व्यवस्था विकसित करना और बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत करना समय की मांग है।

साथ ही, ऊर्जा परिवर्तन के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों के जंगलों, कृषि भूमि और सामुदायिक संसाधनों का अधिग्रहण भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। स्वच्छ ऊर्जा का विकास तभी न्यायपूर्ण कहा जा सकता है, जब उससे स्थानीय समुदायों के अधिकारों और आजीविका की रक्षा हो। कोप -31 में भारत की भूमिका केवल अपने राष्ट्रीय हितों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। भारत को विकासशील देशों की उस मांग को मजबूती से उठाना चाहिए कि जलवायु संकट के लिए ऐतिहासिक रूप से अधिक जिम्मेदार विकसित देश अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें और विकासशील देशों को पर्याप्त वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित वे समुदाय हैं, जिनका वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में योगदान सबसे कम है। अफ्रीका के गरीब देश, छोटे द्वीपीय राष्ट्र, एशिया के किसान, मछुआरे, आदिवासी और वनवासी समुदाय इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इसलिए जलवायु नीति में समानता और न्याय का सिद्धांत अनिवार्य होना चाहिए।भारत को जलवायु वित्त, तकनीकी हस्तांतरण, अनुकूलन योजनाओं और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के मुद्दों पर स्पष्ट और मजबूत पक्ष रखना चाहिए। इसके साथ ही जंगलों, नदियों, आर्द्रभूमियों और जैव विविधता का संरक्षण राष्ट्रीय जलवायु नीति का केंद्रीय हिस्सा होना चाहिए।भारत के सामने भी यह अवसर है कि वह विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने वाला एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करे। ऐसा विकास जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन न हो, जंगलों और नदियों का विनाश न हो, स्थानीय समुदायों के अधिकार सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित हो। जलवायु परिवर्तन किसी एक देश, सरकार या समाज की समस्या नहीं है। यह पूरी मानवता के अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न है।

गोवर्धन पूजा और पड़वा का पर्व प्रकृति संरक्षण कर्तव्यनिष्ठा और नवचेतना का देता है संदेश

कांतिलाल मांडोत

भारतीय संस्कृति पर्वों की संस्कृति है।दीपावली के पांच पर्वों में गोर्वधन पूजा पर्व प्रकृति सरंक्षण का संदेश तो देता ही है।लेकिन इस दिन से नए साल की शुरुआत का प्रथम सोपान भी है। दीपावली के उल्लास और प्रकाश के बाद आने वाली कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् पड़वा भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखती है। यह दिन नई शुरुआत, मंगलकामना, समृद्धि और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। गुजराती परंपरा में इसी दिन से नववर्ष का शुभारंभ होता है। घरों और मंदिरों में पूजा-अर्चना, अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के आयोजन होते हैं। दीपावली जहां अंधकार पर प्रकाश की विजय का संदेश देती है, वहीं पड़वा का पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, परिवार की खुशहाली और जीवन में नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भारतीय संस्कृति में पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते, बल्कि उनके पीछे जीवन को दिशा देने वाले गहरे विचार भी समाहित रहते हैं। गोवर्धन पूजा इसका सुंदर उदाहरण है। भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत से जुड़ी पौराणिक कथा हमें प्रकृति की महत्ता और मनुष्य के कर्तव्यों का बोध कराती है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में गोकुलवासी वर्षा और कृषि की समृद्धि के लिए इंद्रदेव की पूजा करते थे। बालक श्रीकृष्ण ने लोगों को समझाया कि जीवन का वास्तविक आधार प्रकृति है। पर्वत, वन, धरती, जल और पशुधन मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। इनका संरक्षण और सम्मान करना प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है। श्रीकृष्ण ने गोकुलवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की प्रेरणा दी। इससे इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने गोकुल में लगातार मूसलाधार वर्षा कर दी। चारों ओर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर समस्त गोकुलवासियों और गायों को उसके नीचे सुरक्षित आश्रय प्रदान किया। सात दिनों तक वर्षा होती रही, लेकिन गोवर्धन की शरण में आए लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अंततः इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्रीकृष्ण से क्षमा मांगी।

इस कथा का संदेश केवल चमत्कार तक सीमित नहीं है। इसमें प्रकृति की उपयोगिता और उसके संरक्षण का महान विचार छिपा है। पर्वत वर्षा के जल को संचित करने, वनस्पतियों को आश्रय देने और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गाय और अन्य पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार हैं। भारतीय परंपरा ने प्रकृति के इन सभी उपकारों को सम्मान देने के लिए गोवर्धन पूजा की परंपरा विकसित की। आज जब पर्यावरण असंतुलन, जल संकट, जंगलों की कटाई और प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, तब इस पर्व की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन घरों के आंगन में गोबर से पर्वत का प्रतीक बनाकर उसकी पूजा की जाती है। गायों और पशुधन को सजाया जाता है तथा उनकी सेवा और आरती की जाती है। मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव आयोजित होता है। अनेक प्रकार के पकवान और व्यंजन भगवान को अर्पित किए जाते हैं। अन्नकूट का भाव यह है कि अन्न प्रकृति का अमूल्य उपहार है। किसान अपनी मेहनत, धरती की उर्वरता, जल और अनुकूल मौसम के सहयोग से अन्न पैदा करता है। इसलिए अन्न का सम्मान करना और उसका अपव्यय रोकना भी इस पर्व की महत्वपूर्ण सीख है। पड़वा का पर्व समाज में कर्तव्य और जिम्मेदारी का भी स्मरण कराता है।

श्रीकृष्ण की गोवर्धन कथा में इंद्रदेव को यह समझाया गया कि वर्षा करना और प्रजा का संरक्षण करना उनका दायित्व है। किसी पद पर बैठा व्यक्ति जब अपने कर्तव्य को एहसान समझने लगता है और बदले में प्रशंसा या सम्मान की अपेक्षा करता है, तब वह अपने दायित्व का वास्तविक अर्थ भूल जाता है।

अन्न, प्रकृति और लोकमंगल की भारतीय परंपरा

कुमार कृष्णन

भारतीय पर्व-त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा-पद्धतियों तक सीमित नहीं हैं। उनके भीतर समाज की जीवन-दृष्टि, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, कृषि संस्कृति, लोकविश्वास और सामुदायिक जीवन के अनेक सूत्र छिपे हुए हैं। दीपावली के बाद मनाया जाने वाला गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, बलि प्रतिपदा और गुजराती नववर्ष इसी सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। इन पर्वों का बाहरी स्वरूप भले ही अलग-अलग हो, लेकिन इनके केंद्र में अन्न, समृद्धि, प्रकृति, दानशीलता, पारिवारिक आत्मीयता और नए आरंभ की भावना मौजूद है।

कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाने वाला गोवर्धन पूजा पर्व भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कथा से जुड़ा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, द्वापर युग में ब्रजवासी वर्षा के देवता इंद्र की पूजा किया करते थे। बालक कृष्ण ने उनसे प्रश्न किया कि जिस पर्वत, वन, गौवंश और प्रकृति के संसाधनों से उनके जीवन का वास्तविक आधार तैयार होता है, उनकी उपेक्षा करके केवल इंद्र की पूजा क्यों की जाए? कृष्ण ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का संदेश दिया।

कथा के अनुसार, इंद्र इस परिवर्तन से क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रज में मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। वर्षा से जनजीवन संकट में पड़ गया। तब श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों और उनके पशुधन को उसके नीचे आश्रय दिया। सात दिनों तक सभी लोग पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। अंततः इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपना अहंकार त्याग दिया। इस प्रसंग को गोवर्धन लीला के रूप में याद किया जाता है।

इस कथा का धार्मिक महत्व अपनी जगह है, लेकिन इसका सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश भी व्यापक है। यह मनुष्य को याद दिलाती है कि उसका जीवन प्रकृति से अलग नहीं हो सकता। पर्वत, जंगल, जल, जमीन, वनस्पति और पशुधन मानव सभ्यता के आधार हैं। प्रकृति के संसाधनों के प्रति सम्मान और उनके संरक्षण के बिना जीवन की निरंतरता संभव नहीं है। गोवर्धन पूजा को इस अर्थ में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व भी माना जा सकता है। आज जब विकास के नाम पर पहाड़ों का अंधाधुंध दोहन, जंगलों की कटाई, नदियों का प्रदूषण और जलस्रोतों का विनाश चिंता का विषय बन रहा है, तब गोवर्धन की कथा का संदेश और प्रासंगिक हो जाता है। प्रकृति पर मनुष्य का अधिकार असीमित नहीं हो सकता। विकास की ऐसी अवधारणा, जिसमें पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के हितों की अनदेखी हो, अंततः जीवन के आधार को ही कमजोर करती है। गोवर्धन पूजा हमें प्रकृति के साथ सहअस्तित्व का भाव विकसित करने की प्रेरणा देती है।

ब्रज क्षेत्र में इस दिन गोवर्धन पर्वत की विशेष पूजा होती है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल और गोवर्धन में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या जुटती है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा इस पर्व का विशेष आकर्षण है। श्रद्धालु परिक्रमा मार्ग पर चलते हुए भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं। अनेक स्थानों पर घरों और मंदिरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक आकृति बनाई जाती है। उसे फूलों, दीपों और रंगों से सजाया जाता है। दूध, दही, घी और अन्य सामग्री से पूजा की जाती है। यह परंपरा प्रकृति, पशुधन और ग्रामीण जीवन के पारस्परिक संबंधों को भी अभिव्यक्त करती है। गोवर्धन पूजा के साथ ही अन्नकूट का आयोजन होता है। अन्नकूट का शाब्दिक अर्थ अन्न का पहाड़ या विभिन्न खाद्य पदार्थों का विशाल समूह है। इस अवसर पर मंदिरों और घरों में अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। दाल, चावल, सब्जियां, पूड़ी, कढ़ी, मिठाइयां और दूध से बने पकवान भगवान को अर्पित किए जाते हैं। कई मंदिरों में छप्पन भोग की परंपरा भी देखने को मिलती है। भगवान को भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया जाता है।

अन्नकूट की परंपरा में केवल धार्मिक श्रद्धा नहीं, बल्कि अन्न के प्रति सम्मान का भाव भी समाहित है। भारतीय समाज में अन्न को जीवन का आधार और ईश्वर का प्रसाद माना गया है। किसान खेतों में कठिन परिश्रम करके अन्न पैदा करता है। प्रकृति की अनुकूलता, जल, मिट्टी, बीज और श्रम के सम्मिलित योगदान से भोजन हमारी थाली तक पहुंचता है। अन्नकूट इस पूरी प्रक्रिया के प्रति सामूहिक कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है।

इस पर्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष भोजन की साझेदारी है। मंदिरों में तैयार प्रसाद अनेक लोगों के बीच वितरित होता है। सामूहिक भोजन सामाजिक भेदभाव को कम करने और लोगों के बीच आत्मीयता बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। भारतीय लोकजीवन में पर्वों के अवसर पर भोजन बांटने, अतिथियों को आमंत्रित करने और जरूरतमंदों की सहायता करने की परंपरा रही है। अन्नकूट का वास्तविक सामाजिक अर्थ तभी सार्थक होगा, जब अन्न की यह प्रचुरता समाज के उन लोगों तक भी पहुंचे, जिन्हें दो वक्त का भोजन जुटाने में कठिनाई होती है।

आज देश में एक ओर खाद्यान्न उत्पादन और भंडारण की क्षमता बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर कुपोषण, खाद्य असुरक्षा और किसानों की आर्थिक कठिनाइयां बनी हुई हैं। ऐसे समय में अन्नकूट हमें यह सोचने का अवसर देता है कि भोजन केवल उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन का अधिकार है। भोजन की बर्बादी रोकना, किसानों के श्रम का सम्मान करना और जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाना भी इस पर्व की भावना का हिस्सा होना चाहिए।

गोवर्धन पूजा का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष गौवंश की पूजा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय और बैल का विशेष महत्व रहा है। कृषि कार्य, दूध, गोबर, जैविक खाद और ग्रामीण आजीविका में पशुधन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस दिन गायों और बैलों को स्नान कराया जाता है, उनके सींगों को रंगा जाता है, गले में माला पहनाई जाती है और उन्हें विशेष भोजन दिया जाता है। कई क्षेत्रों में इसे गोपूजा और पशुधन के प्रति कृतज्ञता के रूप में मनाया जाता है। हालांकि पशुओं के प्रति सम्मान केवल एक दिन के अनुष्ठान तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उनके लिए पर्याप्त चारा, पानी, चिकित्सा और सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था करना भी समाज की जिम्मेदारी है। पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और किसानों की आजीविका से उसका सीधा संबंध है। गोवर्धन पूजा का संदेश पशुओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार और उनकी उपयोगिता को समझने की प्रेरणा देता है।

इसी तिथि को देश के अनेक हिस्सों में बलि प्रतिपदा या बलि पड़वा भी मनाई जाती है। यह पर्व राजा महाबलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा से संबंधित है। राजा बलि का चरित्र भारतीय पौराणिक परंपरा में दानशीलता, वचनबद्धता और प्रजावत्सलता के लिए विशेष स्थान रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद राजा बलि सात्त्विक विचारों वाले, उदार और अत्यंत दानवीर शासक थे। उन्होंने अपने पुण्य कर्मों और समर्पण से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की।

राजा बलि के द्वार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था।



सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत भी संवारता है
आयोडीनयुक्त नमक



हमारे घरों में सुबह से लेकर रात तक बनने वाले लगभग हर खाने में नमक का इस्तेमाल होता है। दाल हो, सब्जी हो, या सलाद हो, नमक के बिना खाने का स्वाद अधूरा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोजाना इस्तेमाल होने वाले नमक में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा है या नहीं? यह सवाल इसलिए जरूरी है, क्योंकि आयोडीन की कमी शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती है। इसका असर थायरॉइड ग्रंथि से लेकर बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास तक पर पड़ सकता है। इसी महत्व को समझाने और लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। आयोडीन एक जरूरी पोषक तत्व है, जिसकी शरीर को थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। यह थायरॉइड ग्रंथि को थायरॉइड हार्मोन बनाने में मदद करता है। ये हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया, शरीर के तापमान और सामान्य विकास को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब शरीर को पर्याप्त आयोडीन नहीं मिलता तो थायरॉइड ग्रंथि जरूरी मात्रा में हार्मोन नहीं बना पाती। इससे हाइपोथायरायडिज्म जैसी समस्या हो सकती है। इसके कारण थकान, सुस्ती, वजन बढ़ना, ठंड ज्यादा लगना और काम करने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

आयोडीन की कमी का एक परिणाम घेंघा रोग भी है। इस स्थिति में थायरॉइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है और गर्दन के सामने सूजन दिखाई दे सकती है। लंबे समय तक आयोडीन की कमी रहने पर शरीर के सामान्य कामकाज पर भी असर पड़ सकता है।गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की जरूरत विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे का मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र विकसित हो रहा होता है। इस समय गंभीर आयोडीन की कमी बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ मामलों में गर्भपात, समय से पहले प्रसव और अन्य गंभीर जटिलताओं का खतरा भी बढ़ सकता है। शिशुओं और छोटे बच्चों में आयोडीन की कमी सीखने-समझने की क्षमता और विकास को प्रभावित कर सकती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। हालांकि, जरूरत से ज्यादा आयोडीन लेना भी नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना आयोडीन सप्लीमेंट लेना सही नहीं है। आयोडीन की कमी से बचने का एक आसान तरीका रोजा

ना आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना है। नमक खरीदते समय पैकेट पर आयोडीन युक्त होने की जानकारी जरूर देखें। नमक को नमी और गर्मी से बचाकर बंद डिब्बे में रखना चाहिए, ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। भोजन में नमक की मात्रा सीमित रखें, क्योंकि आयोडीन की जरूरत पूरी करने के लिए ज्यादा नमक खाना सही नहीं है।

अत्यधिक नमक का सेवन उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है। दूध, दही, अंडे और कुछ समुद्री खाद्य पदार्थों में भी आयोडीन पाया जाता है। इसकी मात्रा खाद्य पदार्थ के प्रकार और उत्पादन के तरीके पर निर्भर करती है।

संतुलित आहार और आयोडीन युक्त नमक का उचित इस्तेमाल शरीर की जरूरत पूरी करने में मदद कर सकता है।वहीं, गर्भावस्था में आयोडीन की गंभीर कमी होने पर गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में आयोडीन की कमी को हल्के में लेना सही नहीं है। आयोडीन की कमी से बचने का एक आसान तरीका है रोजाना खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना। यह शरीर में आयोडीन की जरूरत पूरी करने में मदद करता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि नमक ज्यादा खाया जाए। अधिक नमक खाने से उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए नमक का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना चाहिए। आयुष मंत्रालय की मानें तो दूध और दही, दालें, कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां, आलू और बीज जैसे तिल, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज में भी कुछ मात्रा में आयोडीन पाया जाता है।

हमारे घरों में सुबह से लेकर रात तक बनने वाले लगभग हर खाने में नमक का इस्तेमाल होता है। दाल हो, सब्जी हो, या सलाद हो, नमक के बिना खाने का स्वाद अधूरा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोजाना इस्तेमाल होने वाले नमक में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा है या नहीं? यह सवाल इसलिए जरूरी है, क्योंकि आयोडीन की कमी शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती है।

हॉर्मोन को रेगुलेट कर बोन हेल्थ में सुधार करते हैं काले तिल



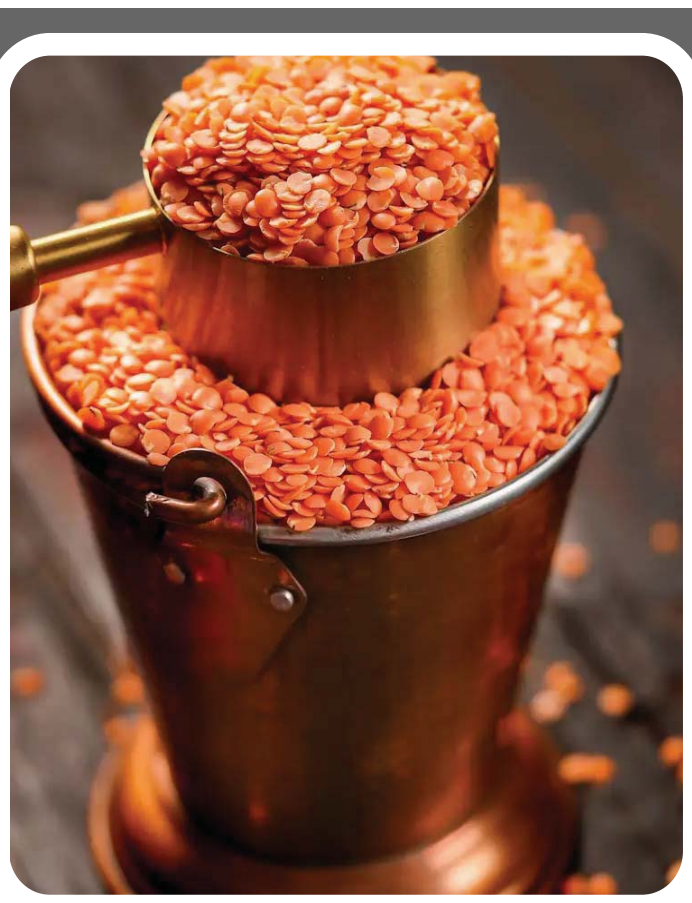
काला तिल न सिर्फ पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है, बल्कि प्रसाद के रूप में इसका सेवन कर खुद को स्वस्थ भी रखा जाता है। पितृ पक्ष में कई आहार का खूब सेवन किया जाता है, तो कुछ खाद्य पदार्थ के सेवन की मनाही की जाती है। किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन करना और नहीं करना पूरी तरह मौसम और वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाता है। परंपरा के साथ इसे इसलिए जोड़ा जाता है, ताकि जरूरी मानकर ऐसा कर लिया जाये। 15 दिन तक चलने वाले पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष में काले तिल का खूब प्रयोग किया जाता है। तर्पण के दौरान इसे पूर्वजों को भी अर्पित किया जाता है। इसके फायदेजानने से पहले जानते हैं पितृ पक्ष में तिल के प्रयोग के कारण।**क्यों होता है तिल का प्रयोग-** भाद्रपद पूर्णिमा के बाद शुरू होता है 16 दिनों का पितृ पक्ष। इस अवधि में मृत पूर्वजों की पूजा-आराधना की जाती है। काले तिल के साथ जल का तर्पण किया जाता है। तिल को प्रसाद रूप में बांटा और खाया भी जाता है। पितृ पक्ष के दौरान तेजी से मौसम बदलते हैं। इसके कारण शरीर में भी मौसमी बदलाव के कारण होने वाले बदलाव से गुजरता है। तिल न सिर्फ इम्यून सिस्टम को मजबूत कर शरीर को मौसमी बीमारियों से बचाता है, बल्कि शरीर को गर्म भी रखता है। **ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है** -न्यूट्रीएंट जर्नल के अनुसार, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, फास्फोरस, पोटैशियम और जिंक जैसे मिनरल्स से भरपूर होते हैं काला तिल। यह दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। काले तिल के तेल का उपयोग कुछ मामलों में ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में भी किया जाता है। काला तिल ऑक्सीडेटिव तनाव कम करता है। इसलिए क्रोनिक डिजीज से पीड़ित लोगों को यह फायदा पहुंचाता है। **महिलाओं के लिए काले तिल के फायदे** -फूड केमिस्ट्री जर्नल के अनुसार, काले तिल आहार फाइबर का एक अच्छा स्रोत हैं। ये स्वस्थ पाचन और नियमित मल त्याग को बढ़ावा देते हैं। फाइबर पाचन में सहायता करता है, कब्ज को रोकता है और स्वस्थ आंत वातावरण बनाता है। काले तिल में हार्मोन को रेगुलेट करने के गुण होते हैं, खासकर महिलाओं में।अलसी के बीज की तरह काले तिल के बीज में भी लिगनेन का हाई लेवल मौजूद होता है। इसलिए यह एस्ट्रोजन बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों की श्रेणी में आता है। खाना पकाने में तिल के तेल का उपयोग किया जाए, तो भोजन के माध्यम से एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।



काले तिल का उपयोग कैसे करें-काले तिल का प्रयोग कई तरह से किया जा सकता है। ध्यान रखें कि हेल्दी वे में इसका प्रयोग करने पर शरीर को अधिक फायदे मिलते हैं।



सस्ती, सेहतमंद और सौंदर्य के लिए भी फायदेमंद है मसूर की दाल



सोयाबीन से भी अधिक प्रोटीन दे सकता है मसूर और मसूर की दाल। सस्ती होने के साथ-साथ यह सेहतमंद भी है। पोषक तत्वों से भरपूर मसूर स्किन हेल्थ के साथ-साथ पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। विशेषज्ञ बताती हैं कि फायदों के लिए इसे सही तरीके से पकाना जरूरी है।दुनिया भर में सबसे अधिक दाल खाई जाती है। यह लंबे समय से उपयोग में आता रहा है। स्वास्थ्य फायदों के कारण मसूर की दाल का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता रहा है। पहली बार मसूर की दाल को 8,000 ईसा पूर्व में उगाया और खाया गया था। हाई प्रोटीन डाइट होने के कारण इसे अलग-अलग रूपों में पकाकर खाया जाता है। मसूर संपूर्ण शरीर के लिए फायदेमंद है।

पोषक तत्वों से भरपूर-प्राइमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डाइटीशियन इन चार्ज अंकिता घोषाल बिष्ट बताती हैं, 'यह ग्लूटेन-मुक्त होता है। इसलिए रॉ मसूर लाल मसूर और मसूर की दाल के रूप में भी यह पसंद किया जाता है। इसमें बहुत सारा पोषण होता है। इसे अन्य सामग्रियों और सीज़निंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है। डेढ़ कप पकी हुई दाल में 140 कैलोरी और वसा 0.5 ग्राम, कार्ब्स- 23 ग्राम, फाइबर 9 ग्राम, सोडियम 5 मिलीग्राम, प्रोटीन 12 ग्राम मौजूद होता है। इनके अलावा, कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम, फोलेट भी होता है।'

यहां हैं मसूर और मसूर की दाल के फायदे

1 दिल के लिए फायदेमंद - अंकिता घोषाल बिष्ट के अनुसार, जब अन्य बीन्स से इसकी तुलना की जाती है, तो यह सोयाबीन के बाद सबसे अधिक प्रोटीन देता है। वीगन डाइट के तौर पर यह मशहूर होने के कारण यह वीगन मीट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप रेड या प्रोसेस्ड मीट के बजाय मसूर दाल का चुनाव करती हैं, तो आप अपने दिल के लिए एक स्वस्थ विकल्प चुनती हैं। फोलेट दिल की रक्षा करता है और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है।

2 हड्डियों और मांसपेशियों के लिए फायदेमंद -अंकिता घोषाल बिष्ट कहती हैं, 'प्रोटीन हड्डियों, मांसपेशियों और स्किन के लिए फायदेमंद है। यह भूख को भी कम कर सकता है, क्योंकि यह अन्य पोषक तत्वों की तुलना में लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। इसमें मौजूद फाइबर पेट भर देता है। दाल में यह प्रचुर मात्रा में होता है। एक सर्विंग से प्रतिदिन जरूरी 32त्न फाइबर की पूर्ति हो जाती है।'

3 पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद -यह कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। यह मधुमेह और पेट के कैंसर से बचा सकता है। फाइबर की दैनिक खुराक पाचन तंत्र के माध्यम से अपशिष्ट को बाहर निकालती है और कब्ज से भी बचाती है।

4 पोटैशियम और फोलेट शरीर के लिए जरूरी-दाल में मौजूद पोटैशियम, फोलेट और आयरन भी पूरे शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। पोटैशियम नमक के बुरे प्रभाव को कम करता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए फोलेट जरूरी है। यह बच्चे के विकास में मदद करता है। आयरन थकान दूर करने में मदद करता है।

बहुत अधिक प्रयोग से समस्या -कई लाभ के बावजूद दाल में मौजूद फाइबर को तोड़ना कठिन होता है। इसलिए अगर इसका बहुत अधिक सेवन किया जाता है, तो यह गैस और ऐंठन का कारण बन सकता है।

कैसे पकाएं मसूर -अधिकांश बीन्स के विपरीत मसूर दाल को पकाने से पहले रात भर भिगोने की ज़रूरत नहीं है। बस उन्हें धो लेना चाहिए। पकाने से आधा घंटा पहले पानी में भिगोने से गैरजरूरी स्टार्च निकल जाते हैं। लाल मसूर दाल सबसे तेजी से पकती है। आमतौर पर 5 मिनट में। अन्य किस्मों के लिए आमतौर पर 20 मिनट पकाने की जरूरत पड़ती है।

कैसे खाएं मसूर

दाल के अलावा, साबुत मसूर को पानी में भिगोकर, उबाल लें। कटी प्याज, लहसुन, हरा धनिया, नींबू, नमक, काली मिर्च के साथ इसे मिक्स कर लें। इसे आटे में स्टफ कर खाएं। इस मसाले को सलाद की तरह भी खा सकती हैं। उबले हुए मसूर को तड़का लगाकर लेंटिल ग्रेवी के रूप में खा सकती हैं। इसे कबाब के रूप में तैयार कर भी खा सकती हैं। मसूर को रोटी और चावल के साथ भी खाया जा सकता है।

स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है अंडा जानिये कितनी देर में खा लेना चाहिए उबला हुआ

यह तो सब जानते हैं अंडों में भरपूर पोषक तत्व होते हैं। कई लोग अंडों को सुबह के नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। खासकर फिटनेस फ्रिक लोग उबले हुए अंडों को अपने डाईट का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उबले अंडों को कितनी देर में खा लेना चाहिए और कितनी देर तक इसे स्टोर कर सकते हैं। अंडा पोषण और प्रोटीन से भरपूर होता है। ठंडा हो या गर्म अंडा सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। अंडे को ठीक तरीके से स्टोर करना चाहिए। रेफ्रिजरेट या फ्रीज करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, कि आपको उबले हुए अंडे कितनी देर में खा लेने चाहिए? ज्यादातर लोग नाश्ते में अंडा खाना पसंद करते हैं। अंडा को उबालकर तो कुछ लोग ऑमलेट खाना पसंद करते हैं। उबले हुए अंडे खाने के हैं कई फायदे सेहत के लिए अंडा अच्छा माना जाता है। यह कई सारे पोषक तत्व से भरपूर होता है। साथ ही साथ यह शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखता है। अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए, बी 6, बी 12, फोलेट, एमिनो एसिड, फास्फोरस और सेलेनियम एसेंशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स (लिनोलिक, ओलिक एसिड) होते हैं। सख्त उबले हुए अंडे प्रोटीन और पोषक तत्व का अच्छा सोर्स हैं। नाश्ते से लेकर स्नैक्स तक में अंडा सबसे शानदार है।

कितनी देर में खा लेना चाहिए उबला हुआ अंडा?अंडे को ज्यादा वक्त तक फ्रेश रखने के लिए फ्रीज में रखा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि उबले हुए अंडे को कितनी देर में खा लेना चाहिए? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सख्त उबले हुए अंडे को आप 5-7 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और आराम से इसे खा सकते हैं। सेहत पर इसका कोई साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेगा।अंडों को उबालने के बाद अगर ज्यादा देर तक सेवन नहीं किया जा रहा, तो जरूरी है कि आप इसके छिलके को ना उतारें। क्योंकि ऐसा करने से अंडे की अंदरूनी परत खुल जाएगी और वह हवा के साथ खतरनाक बैक्टीरिया के संपर्क में भी आ सकते हैं।

फटे अंडे को तुरन्त खा लें-अगर आप उबले हुए अंडे का सेवन तुरंत नहीं करने वाले तो आप इसका छिलका ना उतारें। जब आपको अंडा खाना हो तभी इसके छिलके को उतारें और तुरंत खा लें। इससे यह बैक्टीरिया के संपर्क में नहीं आएगा। अगर अंडा उबालते समय फट गया है तो इसे तुरंत खा लें। इसे फ्रिज में रखने की भूल ना करें।

7 दिन तक खाने योग्य रहता है अंडा-ऐसा कई बार होता है कि अंडे को फ्रिज में रखने के बाद कुछ चीजों की वजह से इसके खराब होने का शक रहता है। लेकिन बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का कहना है कि जब अंडे को सही तरह से स्टोर किया गया हो तो यह 7 दिन तक खाने योग्य रहता है।

CJP के सौरव दास का बड़ा बयान, '...चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस-आप'

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में हो रहे डेयरी फॉर्मर्स के मार्च को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इसे लेकर कई राजनीतिक पार्टियों को एक साथ निशाने पर लिया है. सौरव दास ने कहा, 'किसी भी सरकार को चाहे वह भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी (AAP) हो या कोई और- इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए कि वे दिन दहाड़े चुनाव चुराने को जायज समझें! लोगों को सत्ता अपने हाथों में वापस लेनी होगी! युवाओं को सत्ता वापस लेनी होगी!



उन्होंने कहा, 'लोग अब यह बात समझ चुके हैं कि इस सरकार ने पूरी और अनंत सत्ता हासिल करने की लालच में देश की स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था को तबाह कर दिया है. किसी की भी सरकार हो, चाहे वह BJP की हो, कांग्रेस की, या आम आदमी पार्टी की या किसी अन्य पार्टी की- इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वह खुलेआम चुनावों में धांधली करने की हिम्मत जुटा सके!

सौरव दास ने कहा, 'अब लोगों को सत्ता अपने हाथों में वापस लेनी होगी. युवाओं को आगे आकर सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेनी होगी!

CJP के सह-संयोजक का यह बयान संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके की तरफ से दिए गए उस बयान के कुछ वक्त बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने कोल्हापुर के डेयरी फॉर्मर्स के समर्थन में टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है. दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए गए पोस्ट में इस मामले को लेकर 3 बिंदुओं में जानकारी दी और BJP पर आरोप भी लगाया है. उन्होंने पोस्ट में कहा, 'जो लोग ये सोच रहे हैं कि कोल्हापुर की गोकुल डेयरी में क्या चल रहा है, इसे समझिए:

गोकुल डेयरी के लिए चुनाव हुए थे. सतेज पाटिल के गुट ने 13 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया, जबकि BJP के नेतृत्व वाली महायुति को 12 सीटें मिलीं और वो चुनाव हार गई.

चुनाव में हार मिलने के बाद BJP सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जिसके तहत वोट का अधिकार रखने वाले 4 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया.

इन 4 अतिरिक्त सदस्यों के वोटों के दम पर BJP समर्थित गुट बहुमत हासिल कर सकता है और चुनाव हारने के बावजूद गोकुल डेयरी पर कब्जा कर सकता है. अभिजीत दीपके ने इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'सोचिए, जब एक डेयरी कॉपरेटिव के चुनाव में मिले जनादेश को पलटने के लिए ये इतने उतावले होकर कोशिशें कर रहे हैं, तो ज्ञानेश कुमार (CEC) की मदद से राज्य के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ कर रहे होंगे!'

मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा! पोल से टकराई कार, 6 लोग जिंदा जले



मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. पानीपत-खटीमा नेशनल हाईवे पर जागाहेड़ी के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार सड़क किनारे लगे लाइट पोल से टकरा गई. टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई. जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह एक कार पानीपत-खटीमा नेशनल हाईवे से गुजर रही थी. इसी दौरान जागाहेड़ी के निकट अचानक कार अनियंत्रित हो गई और हाईवे पर लगे लाइट पोल से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में आग लग गई.

हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए कार में मौजूद सभी छह लोगों के शवों को बाहर निकलवाया. इसके बाद शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया.

जानकारी के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग हरियाणा के जींद जिले के निवासी बताए जा रहे हैं. मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है, जिसकी उम्र करीब 10 से 12 वर्ष बताई जा रही है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मृतकों की पहचान पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है और उनके परिजनों से संपर्क करने का प्रोसेस भी जारी है. इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. मृतकों में कार ड्राइवर के अलावा 10 से 12 साल की उम्र का एक बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है.

फिलहाल, पुलिस हादसे के पीछे की वजहों की जांच में जुटी है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कार अनियंत्रित कैसे हुई और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ. इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है. एक ही कार में सवार छह लोगों की मौत से हर कोई स्तब्ध है.

'पीएम ने हमें नक्सली कहा, लेकिन मैं डिबेट के लिए तैयार हूं', राहुल गांधी का पीएम मोदी को चैलेंज

नई दिल्ली। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बस्तर में दिए भाषण के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि प्रिय सीआरपीएफ के जवानों, आपके चेहरों ने सब बता दिया. आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं.

राहुल ने कहा, 'उन्होंने हमें नक्सली कहा. मेरी चुनौती कायम है. वो मुझसे बहस करें. देशद्रोही कौन हैं. विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन चल रहा है. कोई भी समय, किसी भी जगह. मेरी गारंटी. उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी.



राहुल गांधी ने पीएम मोदी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें वह बस्तर के करणपुर स्थित कोबरा ऑपरेशंस बेस में सीआरपीएफ के जवानों के साथ रविवार को दिपावली मनाने पहुंचे थे. यहां पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, 'हमें एक बात याद रखनी चाहिए. नक्सली खत्म हो गए हैं. लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. जंगलों से हथियारबंद नक्सलियों का सफाया तो हो गया, लेकिन दिमागी नक्सलियों ने कई संगठनों पर कब्जा कर लिया है.

उन्होंने कहा कि आज भी वे लोगों को देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ भड़का रहे हैं. इन दिमागी नक्सलियों ने कई राजनीतिक दलों और अलग-अलग संगठनों में भी घुसपैठ कर ली.

योगी ने SIR में हिंदुओं के नाम कटने की बात कही तो अखिलेश यादव बोले- आधार कार्ड से जुड़े वोटिंग

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों सवाल उठाया था कि SIR में एक करोड़ से ज्यादा हिंदू वोटरों के नाम कटे हैं. उन्होंने कहा था कि आखिर क्या वजह है कि जिन लोगों के नाम पंचायत चुनावों की सूची में हैं, उनके नाम लोकसभा और विधानसभा की लिस्ट में क्यों नहीं हैं. इसके अलावा उनका सवाल था कि 50 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं, जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी तो हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है. अब इस मामले में अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने आधार



कार्ड को वोटिंग से जोड़ने की सलाह दी है. अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, 'चुनाव को लेकर सीधी-सरल मांग है. आधार कार्ड को वोटिंग से जोड़ा जाए. काग़ज़ या प्लास्टिक की जगह 'मेटल कार्ड' बनाए जाएं जिससे नक़ली न बन सकें. उंगलियों के निशान या आंख से होने वाली बायोमेट्रिक्स पहचान को अपनाया जाए क्योंकि ये किसी दो व्यक्ति के समान नहीं होते हैं. इसीलिए भाजपा नक़ली वोटिंग नहीं करा पाएगी.' वह पहले भी कह चुके हैं कि आधार कार्ड से वोटिंग को जोड़ दिया जाए. इसके अलावा एसआईआर पर भी वह सवाल उठाते रहे हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलनों में भी वह हिस्सा लेते रहे हैं. योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा था, 'इलेक्शन कमिशन में हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम दिया था. मैं 1 करोड़ 27 लाख उन हिंदू मतदाताओं के बारे में बात कर रहा हूं, जिनके नाम सूची में नहीं हैं. 66 लाख के करीब मतदाता ऐसे हैं, जिनके नाम पंचायत चुनाव की सूची में हैं. लेकिन विधानसभा और लोकसभा की लिस्ट में उनके नाम नहीं हैं. इसी तरह 55 लाख लोग ऐसे हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ तो ले रहे हैं. लेकिन मतदाता सूची से बाहर हैं.' उन्होंने कहा कि 18 से 19 साल के ऐसे साढ़े 4 लाख मतदाता हैं, जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं. यही नहीं उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को तो स्ट्रक ही वापस लेनी की मांग करनी चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगे.

केंद्र सरकार की पहल, कैंसर दवाइयों की कीमतें 96.45 प्रतिशत तक घटीं

केंद्र सरकार की पहल, कैंसर दवाइयों की कीमतें 96.45 प्रतिशत तक घटीं

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि एंटी-कैंसर दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन की संशोधित कीमतें लागू हो गई हैं। साथ ही, 137 एंटी-कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर सीमा तय होने से उपभोक्ताओं को सालाना लगभग 3,540.38 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल के अंतर्गत आने वाले 'नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी' (एनपीपीए) ने 137 एंटी-कैंसर दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर ट्रेड मार्जिन की



सीमा तय कर दी है। यह निर्णय 17 अक्टूबर, 2026 को 'डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज' द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार, 8 नवंबर तक 85 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं से जुड़ी 1,364 एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशन के लिए संशोधित एमआरपी की जानकारी दी थी। मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 679 ब्रांडों ने कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी की है, जबकि एमआरपी में सबसे ज्यादा कमी 96.45 प्रतिशत रही। ये संशोधित एमआरपी 9 नवंबर से लागू हो गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता दवाओं के पैकेट पर छपी संशोधित एमआरपी देख सकते हैं और 'फार्मा सही दाम' मोबाइल एप्लिकेशन या एनपीपीए की वेबसाइट के जरिए कीमतों की पुष्टि कर सकते हैं।

टेस्ट डेब्यू में सबसे तेज अर्धशतक... 20 साल के पाकिस्तानी बल्लेबाज ने रचा इतिहास

नई दिल्ली। इसी साल सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में पाकिस्तान के रजाउल्लाह ने 43 गेंदों में अर्धशतक लगाया था. आज 9 नवंबर को तैयब ने अपने डेब्यू मैच में 46 गेंदों में अर्धशतक लगाया. बता दें कि रजाउल्लाह का ये विस्फोटक अर्धशतक उनके डेब्यू टेस्ट की दूसरी पारी में आया था. उन्होंने 63 गेंदों में 9 छक्के और 4 चौकों की मदद से 81 रन बनाए थे.

पिछले महीने 20 साल के हुए तैयब आरिफ ने श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट की पहली पारी में 57 रन बनाए,



उन्होंने 46 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था. उन्होंने पहले विकेट के लिए आजान अवेस के साथ 86 रनों की साझेदारी कर पाक टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी. अवेस के आउट होने के बाद आए तीनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया. मोहम्मद ताहा ने 51, बाबर आजम ने 50 और पहले दिन का खेल खत्म होने तक सऊद शकील 57 पर नाबाद हैं. बता दें कि मोहम्मद ताहा का भी ये डेब्यू मैच है, जिसमें उन्होंने अर्धशतक जड़ा. रावलपिंडी में खेले जा रहे इस टेस्ट के पहले दिन का खेल खराब लाइट की वजह से जल्दी समाप्त कर दिया गया. पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर 281 रन बना लिए हैं. सऊद शकील 57 और मोहम्मद गाजी घोरी 7 रन बनाकर नाबाद हैं, जो दूसरे दिन पाकिस्तानी पारी को आगे बढ़ाएंगे. श्रीलंका के लिए असीथा फर्नांडो ने 2 विकेट लिए. दिलशान मदुशंका और मिलान रतनायके ने 1-1 विकेट लिया.

'सिर्फ राजनीतिक ड्रामा', शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की खबरों पर तारिक रहमान सरकार का जवाब

नई दिल्ली। शेख हसीना के वापस बांग्लादेश लौटने की अटकलों के बीच तारिक रहमान सरकार ने बड़ा दावा किया है. बांग्लादेश सरकार ने सोमवार (9 नवंबर 2026) को कहा है कि भारत में रह रहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की फिलहाल अपने देश लौटने की कोई मंशा नहीं है. शेख हसीना ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) जारी करने का अनुरोध किया है. इस पर बांग्लादेश के चीफ प्रॉसिक्यूटर मो. अमीनुल इस्लाम ने कहा कि उनकी यह सब कोशिशें सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा हैं. शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्रों के जनआंदोलन के दौरान सत्ता गंवाने के बाद भारत आईं और तब से यहीं रह रही हैं. बांग्लादेश सरकार ने साफ कर दिया है कि उन्हें कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट या नया पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा. विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने उन्हें भगोड़ा बताते हुए पासपोर्ट देने से इनकार किया है. बांग्लादेश ने भारत सरकार से उनके प्रत्यर्पण



की मांग भी की है. भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रत्यर्पण का अनुरोध मिलने की पुष्टि की है और कहा है कि स्थापित प्रक्रियाओं के तहत इस पर विचार और जांच की जा रही है. शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और वहां कानूनी कार्यवाही का सामना करने की इच्छा जताई है. बांग्लादेश अवामी लीग ने अपने आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी. इसके मुताबिक, लंदन स्थित कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के माध्यम से उनके वकीलों ने बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र भेजकर नए दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आग्रह किया है. लेटर में कहा गया है कि अंतरिम प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की ओर से शेख हसीना का मौजूदा बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द किए जाने की खबरें हैं. वकीलों ने उनकी बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत देश के दायित्वों का हवाला देते हुए नए दस्तावेज जारी करने की मांग की है.

हसीना ने पहले भी दिसंबर में स्वदेश लौटने की बात कही थी. विभिन्न मंचों के जरिए उन्होंने कहा था कि वह बांग्लादेश पहुंचकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना चाहती हैं.

ट्रेन में भोजन ऑर्डर करते समय रहें सावधान, आईआरसीटीसी से चेताया

14 अनाधिकृत वेबसाइटों की सूची जारी, सेहत, धोखाधड़ी और डेटा चोरी का खतरा

नई दिल्ली। लंबी दूरी की ट्रेन यात्राओं में अपनी सीट पर गर्मागर्म भोजन का आनंद लेना अब एक सामान्य सुविधा बन गई है, लेकिन इस सुविधा का लाभ उठाते समय यात्रियों को विशेष सावधानी बरती चाहिए। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने ऐसे 14 अनाधिकृत वेबसाइटों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है, जो यात्रियों को स्वास्थ्य जोखिम, ऑनलाइन धोखाधड़ी और व्यक्तिगत डेटा चोरी के खतरे में डाल सकती हैं। यह चेतावनी उन यात्रियों के लिए है जो यात्रा के दौरान भोजन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खाना मांगते हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईआरसीटीसी ने स्पष्ट किया है कि ये अनाधिकृत प्लेटफॉर्म अक्सर ऐसे रेस्टोरेंट से भोजन उपलब्ध कराते हैं जिनके पास न तो जरुरी खाद्य लाइसेंस होते हैं और न ही साफ-सफाई के मानकों का ध्यान रखा जाता है। इससे न केवल खराब गुणवत्ता वाला, बल्कि दूषित भोजन मिलने का खतरा रहता है, जो यात्रियों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालते हैं। स्वास्थ्य जोखिमों के अलावा, इन वेबसाइटों के जरिए ऑर्डर करने पर ऑनलाइन ठगी और संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक खाते का विवरण चोरी होने का भी पूरा अंदेशा रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि यात्री भुगतान कर देते हैं, लेकिन खाना तय समय पर नहीं मिलता या डिलीवर नहीं होता, जिससे उनके पैसे भी डूब जाते हैं।

आईआरसीटीसी ने जिन 14 वेबसाइटों से दूर रहने की सलाह दी है, उनमें रेलरेस्ट्रो.कॉम, रेलरेस्ट्रो.इन, रेलमित्र.कॉम, ट्रैवलखाना.कॉम, ट्रेंसकैफे.कॉम, डिबरेल.कॉम, रेलफूड.नेट, ट्रैवलरफूड.कॉम, फूडऑनट्रैक.इन, ईकैटरिंग.ऐप, खानाऑनलाइन.इन, ट्रेनवे.इन, रेलमील.कॉम और ट्रेनमेनू.कॉम शामिल हैं।

हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा: शोक यात्रा बनी मौत का सफर

हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग जिले में सोमवार को भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए है। यह दर्दनाक हादसा जीटी रोड पर दनुआ घाटी में हथिया बाबा के पास महानेटांड कट के समीप हुआ। मृतक और घायल गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के अटका, बिहारो और सलैया गांव के निवासी थे। वे एक करीबी रिश्तेदार के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए बनारस जा रहे थे। उनकी शोक यात्रा उस समय त्रासदी में बदल गई, जब उनकी सवारी गाड़ी को एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार, वाहन पर रखे शव को बांधने वाली रस्सी ढीली होने के कारण सवारी गाड़ी को सड़क किनारे रोका गया था। लोग रस्सी ठीक करने का प्रयास कर रहे थे, तभी पीछे से आ रहे ट्रेलर ने खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर



रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद, ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। इसी बीच, पीछे से आ रहा कोयला लदा एक ट्रक भी दुर्घटनाग्रस्त वाहन से टकराकर सड़क किनारे घाटी में पलट गया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे। लोगों, पुलिसकर्मियों और एनएचएआई की एंबुलेंस की मदद से घायलों को तत्काल चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद, गंभीर रूप से घायल आठ लोगों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर किया है।

अस्पताल में घायलों के परिजनों की भीड़ से माहौल गमगीन हो गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के सही कारणों व फरार चालक की पहचान के लिए गहन जांच कर रही है।

ट्रंप के पास बड़े फैसले लेने के लिए बचे करीब दो माह

अमेरिकी संसद का सत्र शुरू, रिपब्लिकन बहुमत गंवा चुके हैं दोनों सदनों में

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने और लंबित फैसलों को पूरा करने के लिए करीब दो महीने का समय बचा है। अमेरिकी संसद का सत्र सोमवार से शुरू हुआ है। इस सत्र के दौरान राष्ट्रपति और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के सामने कई महत्वपूर्ण विधायी और राजनीतिक चुनौतियां रहेंगी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रिपब्लिकन पार्टी संसद के दोनों सदनों में अपना बहुमत गंवा चुकी है। हालांकि, नई संसद के सदस्यों के कार्यभार संभालने तक मौजूदा सांसद ही कामकाज जारी रखेंगे। ऐसे में ट्रंप प्रशासन के पास मौजूदा संसदीय व्यवस्था के तहत



अपने प्रस्तावों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का सीमित अवसर होगा।

अमेरिका में संसद के दोनों सदनों का राष्ट्रपति के विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी भी बड़े कानून या नीतिगत प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए संसदीय समर्थन जरूरी होता है। बहुमत की स्थिति बदलने से सरकार के लिए विधायी प्रक्रिया और राजनीतिक सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

आने वाले दो महीने ट्रंप प्रशासन के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि इस दौरान लंबित विधायी प्रस्तावों, सरकारी नीतियों और अन्य महत्वपूर्ण फैसलों पर काम किया जा सकता है। नई संसद के कार्यभार संभालने के बाद राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे और राष्ट्रपति को नए सदन के साथ काम करना होगा। हालांकि, किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी और कितने प्रस्तावों को मंजूरी मिल पाएगी, यह संसदीय समर्थन और राजनीतिक सहमति पर निर्भर करेगा।

यमन में फंसे 19 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला, भारत वापसी की तैयारी

सना। युद्धग्रस्त यमन के होदेइदाह और सना शहरों में पिछले दो हफ्तों से फंसे 19 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। यमन स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सभी नाविक पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं और अब उनकी भारत वापसी की प्रक्रिया जारी है। तनावग्रस्त लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय और दूतावास के इस सफल अभियान से फंसे हुए नाविकों के परिजनों ने राहत की सांस ली है। मीडिया रिपोर्ट में एक पोस्ट में दूतावास ने कहा कि यमन में भारतीय दूतावास ने होदेइदाह और सना में पिछले दो हफ्तों से फंसे 19



भारतीय नाविकों को निकाल लिया है। सभी नाविक सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और भारत लौट रहे हैं। हमारे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग और समर्थन देने के लिए दूतावास सभी संबंधित लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। यह बचाव अभियान ऐसे समय में हुआ है, जब कुछ दिन पहले ही भारत ने बताया था कि यमन के तट के पास एक घटना में शामिल यॉट पर सवार 14 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ये 14 लोग उन्हीं 19 नाविकों में शामिल हैं जिन्हें बाहर निकाला गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 23 अक्टूबर को भारतीय मिशन ने पुष्टि की थी कि होदेइदाह के पास एक यॉट पर सवार सभी 14 भारतीय सुरक्षित हैं। साथ ही यह भी कहा था कि घटना के बारे में जानकारी जुटाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है। इससे पहले कुछ अरब मीडिया रिपोर्टों में हौथी प्रवक्ता याह्या सारी के हवाले से आरोप लगाया गया था कि सऊदी बलों ने यमन के तट के पास लाल सागर में युकार द्वीप के निकट भारतीय यॉट को निशाना बनाया था।

उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ जनपद हरिद्वार में हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाई गई

जनपद के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया जिला स्तरीय मुख्य समारोह का शुभारंभ

- गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन का ऋषिकुल ऑडिटोरियम में हुआ सीधा प्रसारण
- राज्य आंदोलनकारियों को पटका एवं माला पहनाकर किया सम्मानित, विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने दी रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां
- उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, विभिन्न विभागों के लाभार्थियों एवं प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को किया गया सम्मानित

के.के.पी संवाददाता

हरिद्वार। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के



अवसर पर जनपद हरिद्वार में विभिन्न कार्यक्रम हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ आयोजित किए गए। इस अवसर पर ऋषिकुल ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जनपद के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, राज्य आंदोलनकारियों, गणमान्य नागरिकों तथा बड़ी संख्या में आमजन ने



प्रतिभाग किया। समारोह के दौरान गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह का सीधा प्रसारण किया गया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं आमजन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन को देखा तथा प्रदेश की विकास यात्रा और उपलब्धियों से रूबरू हुए। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राज्य आंदोलनकारियों को पटका एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्य निर्माण के लिए उनके संघर्ष, त्याग एवं बलिदान को याद करते हुए उनके योगदान की सराहना की गई। वहीं, विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने उत्तराखण्ड की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं, लोकगीतों एवं लोकनृत्यों पर आधारित मनमोहक प्रस्तुतियों से समारोह में उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने अपने संबोधन में प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम है।

ऑपरेशन प्रहार अभियान के अन्तर्गत हरिद्वार पुलिस की कार्रवाई

शांति व्यवस्था भंग करने पर 03आरोपितों के विरुद्ध की गई कार्रवाई



के.के.पी संवाददाता

कोतवाली झबरेडा। दिनाँक 9/11/26 को एमडीटी पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम शीतलपुर में दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो रहा है जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि एक व्यक्ति अपनी बहन को घर ले जाने के लिए व महिला का पति व ससुर उसको नहीं ले जाने के लिए आपस में आमदा फसाद थे और एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू थे ।

पुलिस कर्म0 गणो द्वारा काफी समझाने का प्रयास किया गया किन्तु नही माने अब्दुल गफ्फार, तारीक, सुहेल को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में हिरासत पुलिस लिया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाई की जा रही है।

नाम पता आरोपित

1- अब्दुल गफ्फार पुत्र इस्लाम
2-तारीक पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी गंज ग्राम शीतलपुर कोतवाली झबरेड़ा(हरिद्वार।)
3- सुहेल पुत्र शौकत निवासीऊ ग्राम बेलड़ा जुनारदार थाना नांगल जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)

कुंभ-2027 की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त ने किया स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

घाटों के शेष निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के कार्य शीघ्र पूरे करने के निर्देश

- सभी सेक्टरों में अस्थाई व्यवस्थाओं के कार्य समानांतर रूप से संचालित करने पर जोर
- कार्य में देरी पर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई

के.के.पी संवाददाता

हरिद्वार। आयुक्त गढ़वाल मंडल श्री आनंद स्वरूप ने सोमवार को हरिद्वार भ्रमण के दौरान कुंभ मेला-2027 की तैयारियों के तहत संचालित विभिन्न निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने डाम कोठी में अधिकारियों के साथ बैठक कर कुंभ मेले से जुड़ी निर्माण योजनाओं, आधारभूत सुविधाओं एवं अस्थाई व्यवस्थाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी कार्यों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने तथा श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगमता और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के



निर्देश दिए।

मंडलायुक्त ने सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी राज्य अतिथि गृह, हरिद्वार में चल रहे अनुरक्षण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुंभ मेला शुरू होने से पहले अतिथि गृह को पूरी तरह सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित कर लिया जाए, ताकि मेले के दौरान यहां आने वाले अतिथियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहें। इसके पश्चात उन्होंने भगत सिंह चौक क्षेत्र में निर्माणाधीन फुटपाथ का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के साथ ही पैदल यात्रियों की सुगम एवं सुरक्षित आवाजाही के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मंडलायुक्त ने इसके बाद अमरापुर घाट एवं नगर निगम घाट पर चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कुंभ क्षेत्र में घाटों के नवनिर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों



की प्रगति की जानकारी ली। गंगा नहर की क्लोजर अवधि के दौरान घाटों के जलमग्न रहने वाले हिस्सों के निर्माण एवं मरम्मत के कार्य पूरे किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने शेष निर्माण कार्यों के साथ ही घाटों की साज-सज्जा एवं सौंदर्यीकरण के कार्य भी अविलंब पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को अमरापुर घाट के निकट कांवड़ पटरी से सटे हरित क्षेत्र की रेलिंग की पेंटिंग कराने तथा पूरे क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। साथ ही सीवर लाइन के लिए निर्मित पुल का रंग-रोगन कराने को भी कहा।

मंडलायुक्त ने बैरागी कैंप, दक्षद्वीप, सतीद्वीप एवं गौरीशंकर क्षेत्र में कुंभ शिविरों की स्थापना के लिए संचालित अस्थाई कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में सड़कों, पार्किंग, अस्थाई पुलों, पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए।

'फिल्मी कहानी', चीन ने Nvidia के CEO हुआंग के बयान के बाद दी प्रतिक्रिया, कहा- सब झूठा

नई दिल्ली। चीन ने एनवीडिया के सीईओ जेन्सन हुआंग पर लगे जासूसी से जुड़े सभी आरोपों को खारिज कर दिया. हुआंग का चीन की कथित जासूस एलिस हुआंग के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था. इस मामले को लेकर आरोप है कि एलिस ने एनवीडिया के सीईओ से दोस्ती बढ़ाकर कंपनी की कई सीक्रेट जानकारी बीजिंग तक पहुंचाई है. हालांकि बीजिंग ने इन सभी आरोपों को झूठा करार दिया है.

ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, चीन के विदेश मंत्रालय ने एनवीडिया के सीईओ और कथिन चीनी जासूस के संबंधों की खबरों को झूठा करार दिया है. विदेश मंत्रालय ने 30 अक्टूबर को इन आरोपों को खारिज करते हुए संबंधित रिपोर्टों को निराधार बताया. उसने इसे चीन के खिलाफ महज एक करार दिया. दावा किया जा रहा है कि चीनी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह एक शानदार कहानी है, जिसमें हॉलीवुड की किसी थ्रिलर फिल्म की तरह सारे मोड़ और सस्पेंस मौजूद हैं. चीन ने कहा कि इन आरोपों को साबित करने के लिए अभी तक कोई भी सबूत नहीं दिखाया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के दावे पूरी तरह से अज्ञात स्रोतों पर निर्भर हैं.

वहीं सिंगापुर के गृह मंत्रालय ने भी 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि सिंगापुर के अधिकारियों को चिंताएं थीं और उन्होंने सिंगापुर स्थित डेटा सेंटर कंपनी 'मेगास्पीड' से जुड़ी एक व्यवसायी महिला की



जांच की थी. मंत्रालय ने कहा कि न तो सिंगापुर सरकार और न ही उसके अधिकारियों ने ऐसा कहा है और ऐसी कोई जांच नहीं हुई थी. बता दें कि एनवीडिया के सीईओ की मीडिया में खबर आने के बाद कई देशों में हलचल तेज हो गई है. चीन पर जासूसी के आरोप लग रहे हैं, लेकिन चीन ने इन्हें गलत करार दिया है.

ईरान युद्ध पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की टिप्पणी से कई अमेरिकन लोग नाराज

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की हालिया टिप्पणियों को कई लोगों ने पसंद नहीं किया है। वेंस ने पिछले सप्ताह हुए मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार के बाद सोशल मीडिया पोस्ट किया था। उन्होंने चुनाव में करारी हार के लिए ईरान से युद्ध को जिम्मेदार ठहराया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि एक बात को छोड़कर, वे सही थे। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें एक और बात भी कहनी चाहिए थी, अगर आपको फिर से वही फैसला लेना पड़े, तो क्या आप फिर से वही करेंगे? इसका जवाब हां है। ट्रंप से पूछा गया कि क्या वेंस की टिप्पणियों का दोनों नेताओं के रिश्तों पर असर पड़ा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वेंस की बातों से कई लोग



नाराज हुए हैं। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि इतिहास में इसे अमेरिका के सबसे अच्छे फैसलों में से एक माना जाएगा। यदि ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो वह दुनिया को तबाह कर सकता था। ट्रंप ने दावा किया कि यह फैसला इतिहास में अमेरिका के सबसे अच्छे फैसलों में गिना जाएगा, क्योंकि उनके मुताबिक परमाणु हथियार हासिल करने पर ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर 2015 में समझौता हुआ था। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंधों के बदले उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने का प्रावधान था। हालांकि ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया था। ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करने के आरोपों से इनकार करता रहा है। दरअसल कांग्रेस के दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद जेडी वेंस ने एक लंबी पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ अमेरिका संघर्ष हार की वजह बना। शीर्षक हमारी हार की वजह युद्ध है में उन्होंने लिखा- हर कोई जानता है कि हम क्यों हारे और आगे हमें क्या करना चाहिए, इस पर होने वाली किसी भी निष्पक्ष चर्चा की शुरुआत इसी बात से होनी चाहिए। वेंस का मानना है कि ईरान युद्ध की वजह से रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिकी कांग्रेस पर अपना नियंत्रण खो दिया है।

नासा ने आर्टेमिस मिशन के लिए मांगे नए अंतरिक्ष यात्री

न्यूयॉर्क। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने महत्वाकांक्षी आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत चंद्रमा पर मानव बस्ती स्थापित करने के दीर्घकालिक लक्ष्य को साकार करने के लिए नए अंतरिक्ष यात्रियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। जो लोग चांद पर जाने और ऐतिहासिक अभियान का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं, वे 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नासा के अधिकारियों ने कैनेडी स्पेस सेंटर में आयोजित एक एयर शो के दौरान इसकी घोषणा की।

वर्तमान में केवल 32 सक्रिय अंतरिक्ष यात्रियों के साथ, नासा को पृथ्वी की निचली कक्षा से आगे मानव उपस्थिति का विस्तार करने के लिए और कर्मियों की जरुरत है। दो साल पहले हुई पिछली भर्ती में 8,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 10 उम्मीदवारों का चयन सितंबर 2025 में किया गया था। आर्टेमिस-द्वितीय मिशन ने इस साल अप्रैल में चंद्रमा के



चारों ओर चालक दल की उड़ान के साथ अभियान की शुरुआत की थी। आर्टेमिस-तृतीय मिशन के कमांडर रैंडी ब्रेस्निक ने कहा, हमारे पास काम कहीं ज्यादा है और अंतरिक्ष यात्रियों की संख्या कम है। नासा 2027 के अंत तक अंतिम उम्मीदवारों का चयन कर 2028 की शुरुआत में प्रशिक्षण शुरू करने की उम्मीद कर रहा है। इसी साल (2028) नासा की योजना आधी सदी से अधिक समय बाद फिर से अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भेजने की है। ब्रेस्निक ने संभावित उम्मीदवारों से आवेदन में देरी न करने की अपील की। वे अगले साल गर्मियों में अपने तीन साथियों के साथ अंतरिक्ष में जाएंगे, जहाँ वे स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन द्वारा बनाए जा रहे चंद्र लैंडर के साथ अपने अंतरिक्ष यान के कैप्सूल को जोड़ने का अभ्यास करने वाले है।

यह मिशन आर्टेमिस-चतुर्थ की तैयारी है, जिसके तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दो अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने का प्रयास किया जाएगा। नासा की दीर्घकालिक योजना अधिक रोवर, रोबोट और संरचनाएं भेजकर चंद्रमा पर स्थायी बेस विकसित करने की है।

अंताल्या में सीओपी 31 शिखर सम्मेलन शुरू, पुराने वादों को पूरा करने पर रहेगा जोर

अंकारा। तुर्किये के भूमध्यसागरीय तट पर स्थित अंताल्या शहर में संयुक्त राष्ट्र का 31वां जलवायु शिखर सम्मेलन (सीओपी31) शुरू हो गया है। दुनिया भर के नेता, प्रतिनिधि और जलवायु कार्यकर्ता जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर विचार-विमर्श करने वाले है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जलवायु कार्रवाई के लिए नई प्रतिबद्धताएं तय करने के साथ-साथ पहले किए गए वादों को हकीकत में बदलना है। यह तब हो रहा है जब पिछले एक साल में वैश्विक तापमान में वृद्धि, यूरोप में जानलेवा लू और नेपाल में विनाशकारी बाढ़ जैसी आपदाओं ने जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों को उजागर किया है। सम्मेलन जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ईरान में चल रहे संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य का करीब बंद हो जाना शामिल है। इस स्थिति ने पेट्रोल, तेल, उर्वरक और कीटनाशक जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों की वैश्विक कीमतों में वृद्धि की है, जिससे सरकारों को अपनी अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऊर्जा नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस संकट ने पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ाने की अनिवार्यता को भी रेखांकित किया है। यह शिखर सम्मेलन इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जलवायु वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस के पेरिस समझौते के लक्ष्य को पार कर जाएगी।

19वीं सदी की शुरुआत की तुलना में इस सीमा को रोकने का लक्ष्य 2015 में निर्धारित किया गया था, लेकिन ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने में दुनिया की विफलता ने इसे अब व्यावहारिक नहीं रहने दिया है।

'बेवकूफी की भी हद होती है'... अब किस बात पर भड़कीं कॉकरोच जनता पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह



नई दिल्ली। दिवाली के जश्न के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को घने कोहरे और धुंध की चादर छाई रही। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 400 से ज्यादा दर्ज किया गया। दिल्ली की 'जहरीली' हवा पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की लीगल हेड रत्ना सिंह ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। रत्ना सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें एक्यूआई को लेकर जमकर खरी-खरी सुनाई है। रत्ना ने एक्स पोस्ट में कहा 'मैं लखनऊ में हूं और यह सोचकर ही मेरा दिल घबरा रहा है कि मुझे जल्द दिल्ली आना है। मैं यहां किसी किसी को भी दोष नहीं देना चाहती क्योंकि लोगों ने बार-बार यह दिखाया है कि वे अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की सोच पहले ही बदलना बंद हो गई थी। परंपरा, प्रतिष्ठा के नाम पर 'अनुशासन' ही भूल गए हैं लोग। हर साल की यही सिलसिला जारी है। कोर्ट सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाजत देता, दुकानदार ग्रीन पटाखों को छोड़कर सब कुछ बेचते हैं और लोग तब तक पटाखे फोड़ते हैं जब तक उनकी जेब खाली न हो जाए। और फिर पूरी सर्दियों के दौरान प्रदूषण का रोना रोते हैं। वे इसके लिए क तरह के बहाने बनाते हैं या एक-दूसरे के धर्म को जिम्मेदार ठहराते हैं। रत्ना सिंह ने आगे कहा 'भगवान के लिए थोड़े समझदार बनिए। अपने आस-पास देखिए। छोटे बच्चे, जानवर, बुजुर्ग और सड़कों पर रहने वाले उन गरीब लोगों के बारे में सोचिए जो एन-95 मास्क तक नहीं खरीद सकते। 10 एयर प्यूरीफायर तो रही दूर की बात। उनके पास इस जहरीली हवा में सांस लेने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। बेवकूफी की भी हद होती है। पीटीआई के मुताबिक दिल्ली में इस साल दिवाली के दिन पिछले पांच साल में सबसे ज्यादा प्रदूषण दर्ज किया गया और इस दिन औसत एक्यूआई 376 रहा। वहीं दिवाली के अगले दिन सोमवार सुबह 10 बजे एक्यूआई 371 दर्ज किया गया, जो 2021 के बाद दिवाली के अगले दिन का प्रदूषण का सबसे ज्यादा स्तर है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई थी। शहर में रविवार को औसत एक्यूआई 376 दर्ज किया गया जो कि 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा। दिल्ली में अगले कुछ दिन हवा के बेहद खराब रहने की संभावना जताई गई है।

बेंगलुरु में पत्नी ने प्रेमी संग की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर किया गुमराह, ऐसे पकड़ी गई

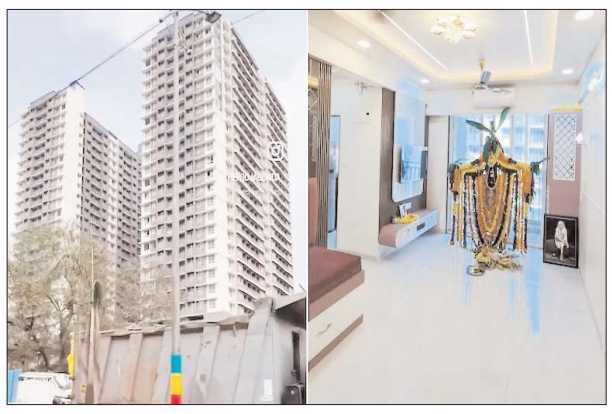


नई दिल्ली। बेंगलुरु में एक शख्स की हत्या करने और फिर उसे हार्ट अटैक बताकर गुमराह करने के आरोप में मृतक की पत्नी सहित दो लोगों को अरेस्ट किया गया है. मामला 12 अक्टूबर 2026 का है जब मृतक के भाई ने ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई. उसने दावा किया कि उसका बड़ा भाई बाथरूम जाते समय फिसलकर गिर गया और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज कर लिया.

हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस को शक हुआ और उन्होंने मौत कैसे हुई इसकी जांच शुरू कर दी. 5 नवंबर को पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया. पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध की बात कबूली. पुलिस ने बताया कि पति को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया था और उसने दोनों को चेतावनी दी थी. पति को अपने रिश्ते में रोड़ा मानते हुए दोनों ने उसे खत्म करने की साजिश रची.

जांच के मुताबिक- आरोपियों ने 12 अक्टूबर की सुबह मृतक का नाक-मुंह दबाकर और गला घोंटकर उसकी जान ले ली. हत्या को छिपाने के लिए उन्होंने कथित तौर पर इसे दुर्घटना बताया और दावा किया कि मृतक को दिल का दौरा पड़ा था.

9 टू 5 जॉब वाली लड़की ने बिना लोन के खरीदा 70 लाख का घर, बताया- बचत का सही फॉर्मूला

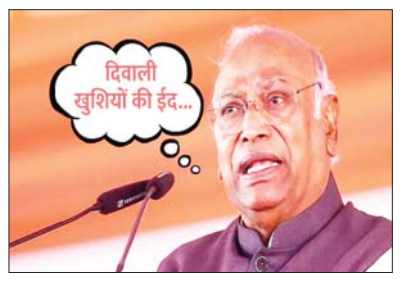


मुंबई। बिना किसी होम लोन के झंझट के अपना घर खरीदना क्या वाकई मुमकिन है? महाराष्ट्र के शहाड़ की रहने वाली एक महिला ने इसे सच कर दिखाया है. उन्होंने बिना कोई कर्ज लिए न सिर्फ 70 लाख रुपये का घर खरीदा, बल्कि उसे शानदार तरीके से सजाया भी. सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी 3 साल की इस अनोखी बचत यात्रा को साझा किया है. महिला ने बताया कि उनका फ्लैट 60 लाख रुपए का था, लेकिन इंटीरियर के साथ कुल खर्च करीब 70 लाख आया. उन्होंने इस पूरी रकम का भुगतान 3 साल में किया. उन्होंने पहले साल 4 लाख, दूसरे साल 5.5 लाख और तीसरे साल 9.5 लाख रुपये बचाए. इसके अलावा, उन्होंने एक लाख का इमरजेंसी फंड भी अलग रखा. उनका सीधा फॉर्मूला था, दो बैंक खाते रखें, एक 'सैलरी अकाउंट' और दूसरा 'ड्रीम अकाउंट' (सपनों का खाता). सैलरी आते ही उसका बड़ा हिस्सा ड्रीम अकाउंट में चला जाता था, जिसका कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं था ताकि फिजूलखर्ची न हो.

शुरुआत में उन्होंने लोन लेने की सोची थी, लेकिन पिता की सलाह पर उन्होंने बिल्डर से सीधे बात की.

चूंकि प्रॉपर्टी बन रही थी, इसलिए उन्होंने बिल्डर को निर्माण के काम से जोड़कर किस्तों में भुगतान करने के लिए मना लिया. तय हुआ कि वह अगले 36 महीनों तक हर महीने एक लाख देंगी और बाकी बचे 8 लाख रुपए पजेशन के समय चुकाएंगी.

'दिवाली खुशियों की ईद...', खरगे के बयान पर सियासी बवाल, बीजेपी ने कांग्रेस को बताया सनातन विरोधी



नई दिल्लीः कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा दिवाली को 'खुशियों की ईद' कहे जाने के बाद सियासी विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी ने खरगे की कड़ी आलोचना करते हुए उन पर वोट-बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति करने और 'सनातन-विरोधी' मानसिकता दिखाने का आरोप लगाया है. इस विवाद ने कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक नई तकरार को जन्म दे दिया है, जिसमें सत्ताधारी दल ने त्योहार पर किए गए बयान को लेकर कांग्रेस प्रमुख को निशाना बनाया है. दरअसल, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दिवाली के मौके पर मीडिया के साथ बातचीत में कुछ ऐसा कह दिया, जिस पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है. उन्होंने यह बयान दिवाली की बधाई देते हुए दिया. मीडिया से बात करते हुए खरगे ने कहा, 'मैं सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं. यह बहुत बड़ा त्योहार है, जिसको हिंदुस्तान में सभी लोग मनाते हैं. इसका एक ही कारण है कि यह खुशियों की ईद है. लंबे वक्त तक चलने वाली ईद यही है. बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा, 'कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का दिवाली पर दिया गया टेढ़ा-मेढ़ा संदेश इस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की अपनी जहरीली वोट बैंक राजनीति को साधने के लिए, करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाने या उनका अपमान करने से कभी पीछे नहीं हटती. ये वही खरगे जी हैं, जिन्होंने महाकुंभ का अपमानजनक तरीके से मजाक उड़ाया था. उन्होंने आगे कहा कि हमारा देश कभी नहीं भूलेगा और न ही कभी माफ करेगा कि किस तरह राहुल गांधी ने छठ पूजा का भद्दा अपमान करते हुए उसे महज़ एक 'ड्रामा' करार दिया था. नेहरू की कांग्रेस से लेकर, जिसने भव्य सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया था, राहुल गांधी की कांग्रेस तक, जिसने भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को दुर्भावनापूर्ण तरीके से 'नाच-गाना' बताकर उसका अपमान किया, कांग्रेस पार्टी लगातार हिंदू-विरोधी मानसिकता पाले हुए है. तुष्टीकरण की अपनी बांटने वाली वोट बैंक राजनीति को बढ़ावा दे रही है.

काम की बातः दिल्ली में लागू हुआ नया कानून; समय पर काम नहीं होने पर अफसरों पर लगेगा जुर्माना



नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं को समय पर मुहैया कराने के साथ ही पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए 'एक नया कानून' अधिसूचित किया है। दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026' अधिसूचित किया है। इसका मकसद सरकारी सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और सुगम बनाना है। यह कानून 2011 के पुराने नियम की जगह लेगा। अब निर्धारित समय में काम नहीं होने या अनुचित कारण से आवेदन निरस्त करने पर जिम्मेदार अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। नागरिक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे, जिससे दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

दिल्ली में सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकों के लिए सुगम बनाने की दिशा में रेखा गुप्ता सरकार ने 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026' (दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस एक्ट, 2026) को अधिसूचित किया है। इस नए कानून का मकसद सरकारी विभागों में सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा से बांधना और अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। यह अधिनियम वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह लेगा और एक आधुनिक जवाबदेह व्यवस्था लागू कराने में मदद करेगा।

नए कानून के तहत नागरिकों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय के भीतर प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार मिलेगा। सरकार अधिसूचना के माध्यम से यह तय करेगी कि कौन-कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में आएंगी। हर सेवा को उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित की जाएगी। हर सेवा के लिए एक नामित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस कानून के दायरे में संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को लाया जाएगा। अब किसी आवेदन के लंबित रहने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इससे नागरिकों को अनिश्चितकाल तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।

इस कानून के तहत आम लोगों को जानकारी रहेगी कि उनका काम किस अधिकारी को करना है और उसे पूरा करने की समय सीमा क्या है। नए कानून में सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और उनकी ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था की गई है। हर आवेदन को एक विशिष्ट आवेदन संख्या दी जाएगी।

क्या फिर एक होगी NCP? कौन है विलय के पक्ष और कौन विरोध



मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. अजित पवार के निधन के बाद बदले राजनीतिक समीकरण, पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर बढ़ती खींचतान, शरद पवार और अजित गुट के नेताओं की हालिया मुलाकातें, दिल्ली में अमित शाह के साथ हुई बैठक और कुछ बड़े नेताओं के बयानों ने इस चर्चा को शांत होने की जगह और बढ़ा दिया है. हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी पक्ष ने विलय की पुष्टि नहीं की है, लेकिन लगातार हो रहे घटनाक्रमों ने महाराष्ट्र की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है. अहम ये है कि NCP (SP) विधायक रोहित पवार ने सोमवार को कहा- BJP ने परिवार और पार्टी में विभाजन कराया है और उनकी पार्टी का भाजपा के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं है. रोहित पवार ने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म और जाति के नाम पर विवाद पैदा करती है और कुछ ताकतवर लोगों के हितों की राजनीति करती है. पिछले कुछ महीनों से शांत पड़ी विलय की चर्चा हाल के दिनों में फिर सुर्खियों में आ गई है. इसके पीछे कई राजनीतिक और संगठनात्मक कारण बताए जा रहे हैं. राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि दोनों गुटों के नेताओं के बीच बैकचैनल बातचीत जारी है, जबकि कुछ नेता खुलकर इस मुद्दे पर बयान भी देने लगे हैं.

'RSS पर बैन के खिलाफ इब्राहिम ने किया था सपोर्ट', मोहन भागवत ने सुनाया 1930 के दशक का किस्सा



नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को याद दिलाया कि 1930 के दशक में जब सेंट्रल प्रोविंस असेंबली में RSS पर पहली बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी, तब उसका बचाव करने के लिए कोई स्वयंसेवक मौजूद नहीं था. उस समय RSS के समर्थन में केवल एक व्यक्ति की आवाज उठी थी, जिनका नाम इब्राहिम था. आखिर मोहन भागवत किस इब्राहिम के बारे में बात कर रहे हैं जिसने RSS को बैन करने खिलाफ आवाज उठाई थी.

मोहन भागवत सोमवार को नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के रेनोवेट किए मुख्यालय में नए बने सभागार का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे. यहां भागवत ने कहा कि उस समय संघ की विचारधारा का समर्थन करने वाला कोई नहीं था. तब इब्राहिम ने तर्क दिया कि संघ को बंद नहीं किया जाना चाहिए और यह सांप्रदायिक नहीं है.

मोहन भागवत ने कहा, '30 के दशक में, जब सेंट्रल प्रोविंस असेंबली में संघ पर पहली बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई, तो संघ का बचाव करने के लिए कोई स्वयंसेवक नहीं था; संघ की विचारधारा का समर्थन करने वाला भी कोई नहीं था. तब मिस्टर इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति ने संघ के समर्थन में आवाज उठाई. उन्होंने कहा कि संघ को बंद नहीं किया जाना चाहिए और यह सांप्रदायिक नहीं है. मोहन भागवत ने आगे बताया, 'अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा था, 'मेरा मानना है कि जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान एक 'हिंदू राष्ट्र' है, उन्हें तो पागलखाने भेज देना चाहिए. मैं डॉ. हेडगेवार को जानता हूं. वे पागल नहीं हैं, बल्कि एक अच्छे इंसान हैं. इसलिए, संघ सांप्रदायिक नहीं हो सकता.' उस समय संघ बने हुए कुछ ही साल हुए थे. तब संघ के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन डॉ. हेडगेवार को सब जानते थे... जब संघ की शुरुआत हुई, तो स्वयंसेवक ही उसकी पहचान बन गए.

'वोट बैंक की राजनीति करती है SP-कांग्रेस...', अखिलेश-सोनिया पर भड़के ब्रजेश पाठक, सनातन पांडे को भी दिए जवाब



लखनऊः उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का तीखा हमला बोला है. सनातन पांडे के बयान, अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे, शिवपाल यादव के बयान और खरगे के दिवाली-ईद वाले बयान पर उन्होंने कहा कि सपा-कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती हैं, सनातन संस्कृति की कभी पक्षधर नहीं रहीं. सनातन पांडे के बयान पर ब्रजेश पाठक ने कहा, 'समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण के आधार पर जाति की राजनीति करती है. एसपी के मुखिया एक तरफ अयोध्या जाने की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ उनके बड़े नेता कह रहे हैं कि गोली चलाना अच्छी बात थी. समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर बना हुआ राजनीतिक दल है.' उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अयोध्या जाएं, तो एक बार प्रभु रामलला के दर पर जाकर अयोध्या धाम में निहत्थे कारसेवकों पर जो गोलियां चली थीं, उसके संबंध में कान पकड़कर प्रभु रामलला के दरबार में माफी मांगें. उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते. यह गुंडे, बदमाश और माफियाओं को पुष्पित-पल्लवित करने वाली पार्टी है.

शिवपाल यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा, 'इसका मतलब वो देखने वाले हैं. इसका मतलब सरकार आएगी तो गुंडे, बदमाश और माफियाओं को जेल से छोड़ने वाले हैं. मुझे जानकारी मिली है कि जेलों में जश्न मनाया जा रहा है. जिन्हें हमारी सरकार ने जेलों में डाला है, गुंडे-माफिया बाहर निकलकर फिर अत्याचार करने का मन बना रहे हैं. मैं गुंडे-माफियाओं को भी कहता हूं, समाजवादी पार्टी को भी कहता हूं कि तुम्हारा मंसूबा कभी सफल नहीं होगा. '

उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को, कमल को तीसरी बार प्रचंड बहुमत से जिताने का मन बना चुके हैं.

यशस्वी जायसवाल के बदले पूरन, राजस्थान के 3 खिलाड़ी जाएंगे लखनऊ! चौंका देगी ये ट्रेड डील



नई दिल्ली। आईपीएल 2027 के लिए ट्रेड विंडो खुली हुई है. इस नियम के जरिए कई बड़े खिलाड़ियों की अदला-बदली की जा चुकी है. आईपीएल 2027 की ऑक्शन से पहले अब तक आठ ट्रेड डील की जा चुकी हैं. वहीं कुछ बड़ी डील होना बाकी हैं. मुंबई इंडियंस से हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स जाएंगे. उनकी जगह अर्शदीप सिंह पंजाब से मुंबई में आएंगे. इस डील पर मुहर लग चुकी है, लेकिन अभी इसका औपचारिक एलान नहीं हुआ है. अब एक और बड़ी ट्रेड डील सामने आई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़कर लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल होंगे. वहीं लखनऊ से निकोलस पूरन या जोश इंग्लिस राजस्थान आएंगे. इस तरह लखनऊ और राजस्थान के बीच तीन खिलाड़ियों की अदला-बदली होगी. रिपोर्ट में यशस्वी जायसवाल, संदीप शर्मा और विग्नेश पुथुर के लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल होने की संभावना बताई गई है. इस ट्रेड डील के जरिए जोश इंग्लिस या निकोलस पूरन, प्रिंस यादव के साथ राजस्थान रॉयल्स में जा सकते हैं. कुछ दिन पहले राजस्थान और लखनऊ के बीच इस ट्रेड डील को लेकर चर्चा हुई है. हालांकि, अभी तक दोनों ही फ्रेंचाइजी की तरफ से कोई औपचारिक एलान नहीं किया गया है. लखनऊ और राजस्थान की ट्रेड डील के अलावा दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की एक डील भी चर्चा में है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गुजरात ने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के बदले फिनिशर आशुतोष शर्मा को लेने की डील दिल्ली कैपिटल्स को ऑफर की है. हालांकि, इस डील का भी अभी औपचारिक एलान नहीं हुआ है.

अब तक हुई ट्रेड डील की लिस्ट

ऋषभ पंत - लखनऊ सुपर जायंट्स से दिल्ली कैपिटल्स - 15 करोड़
कुलदीप यादव - दिल्ली कैपिटल्स से लखनऊ सुपर जायंट्स - 13.50 करोड़
टी नटराजन - दिल्ली कैपिटल्स से सनराइजर्स हैदराबाद - 5 करोड़
जीशान अंसारी - सनराइजर्स हैदराबाद से दिल्ली कैपिटल्स - 40 लाख
लियाम लिविंगस्टोन - सनराइजर्स हैदराबाद से चेन्नई सुपर किंग्स - 6 करोड़
खलील अहमद - चेन्नई सुपर किंग्स से सनराइजर्स हैदराबाद - 4.8 करोड़
जैक एडवर्ड्स - सनराइजर्स हैदराबाद से चेन्नई सुपर किंग्स - 3 करोड़
नाथन एलिस - चेन्नई सुपर किंग्स से सनराइजर्स हैदराबाद - 2 करोड़

डाना व्हाइट को प्रेस सेक्रेटरी बनाने की बात को ट्रंप ने बताया मजाक

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने बयानों से एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं, जिसमें उन्होंने मजाक में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप (यूएफसी) के सीईओ डाना व्हाइट को व्हाइट हाउस का प्रेस सेक्रेटरी बनाने की बात कही और साथ ही यह भी कहा कि वह नर्क नहीं जाना चाहते। ट्रंप ने एक साक्षात्कार में इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि डाना व्हाइट को प्रेस सेक्रेटरी नियुक्त करने की उनकी सोशल मीडिया पोस्ट सिर्फ एक मजाक थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए था कि मैं बस मजाक कर रहा हूं। डाना व्हाइट को भी यह विचार पसंद आया। डाना जैसा कोई दूसरा नहीं है। वह बहुत शानदार हैं। वैसे भी उनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा, लेकिन, मैं जाहिर तौर पर मजाक कर रहा था। इससे पहले शनिवार को ट्रंप ने अपनी पोस्ट में डाना व्हाइट के अलावा कई प्रमुख फाइटर्स जैसे इस्लाम मखाचेव, खबीब नूरमगोमेदोव, जस्टिन गेथजे, डैनियल कॉर्मियर, अमांडा नून्स और कायला हैरिश का नाम लिया था। उन्होंने लिखा था कि हमें पागल वामपंथियों यानी लूनाटिक लेफ्ट से अपनी रक्षा करने के लिए इन लोगों की जरूरत है।

स्वामी/ प्रकाशक / मुद्रक
प्रमोद कुमार ने जय माँ गंगा प्रिंटर्स, हरिद्वार से मुद्रित कराकर कार्तिकेय कॉलोनी, फेस-3, दर्पण स्कूल वाली गली, निकट हनुमान मंदिर, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी जनपद-नैनीताल (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया।
सम्पादक
प्रमोद कुमार
मो.7830201066
सह-सम्पादक
दया जोशी
मो.9412135616